सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 320, नई दिल्ली । सोमवार, 27 जनवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

कष्ट सहने पर ही हमें अनुभव होता है और दर्द हो, तभी हम सीख पाते हैं।

03 *मन की बात कार्यक्रम सुनते कार्यकताओं के साथ -- सांसद भोला सिंह
06 रिवर्स ब्रेन ड्रेन: विकास के लिए गेम-चेंजर
08 अधिकारियों के वाहन का किराया बढ़ाया गया; जानें कौन कितना मिलेगा पैसा..

दिल्ली चुनाव को लेकर मेट्रो में चर्चा, युवाओं ने बताया किन मुद्दों पर करेंगे मतदान

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में युवा मतदाता रोजगार बेहतर बुनियादी ढांचे और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं। दैनिक जागरण की टीम ने मेट्रो में गोविंदपुरी से बदरपुर तक युवाओं से बातचीत की और उनके चुनावी मुद्दों को जाना। युवाओं का कहना है कि इस बार प्रदेश के विकास पर ध्यान देने वाली सरकार बननी चाहिए।

दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। युवा मतदाता इस बात को लेकर अब चर्चा कर रहे हैं कि रोजगार देने के बारे में न तो कोई दल ही बात कर रहा है और न ही कोई उम्मीदवार। जबकि युवाओं को अब सबसे ज्यादा जरूरत है तो वह रोजगार की है।

दैनिक जागरण की टीम ने विधानसभा चुनाव को लेकर मेट्रो में गोविंदपुरी से बदरपुर और बदरपुर से गोविंदपुरी तक युवाओं से विधानसभा चुनाव में उनके मुद्दों को लेकर चर्चा की। युवाओं का कहना है कि प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान दें। साफ-सफाई हो।

क्या बोले मतदाता?

युवा पढ़ने-लिखने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। अब रोजगार के साधन बहुत सीमित हो गए हैं। युवा पथ भ्रमित हो रहा है। अब अपराध, नशा की तरफ मुड़ रहा है। उनको सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है। ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो रोजगार दे सके। - अंचल झा

दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में सड़कों की हालत जर्जर बनी हुई है। गांवों जैसी स्थिति बन गई है। कई बार दुर्घटना भी घट जाती हैं। सड़कों पर पैचवर्क भी नहीं किया जाता है। इन सड़कों की तरफ ध्यान देने वाली सरकार बननी चाहिए। ताकि दिल्ली को एक अच्छा विकसित शहर बनाया जा सके। -मनोज

दिल्ली में जगह-जगह पर कचरा के ढेर पड़े हुए हैं। जबकि यह देश की राजधानी है। पूरे भारत और विदेशों से लोग यहां पर घूमने के लिए आते हैं। जब वह यहां से कचरा के ढेर देख कर जाते हैं तो अपने वहां जाकर क्या बताते होंगे। इसका अंदाजा लगाना चाहिए। अब ऐसी सरकार बनानी चाहिए जो दिल्ली को साफ-सुंदर बना सके। -साहिल

महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब सीजन में भी सब्जी सस्ती नहीं मिलती है। कम आय वाले व्यक्ति को अपने परिवार का पालन-पोषण करना मुश्किल होता है। ऐसी सरकार बननी चाहिए जो महंगाई को कम कर सके। ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को पेट भरने के लिए भोजन मिल सके। - नरेंद्र कोहली

लोगों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं

दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र स्थित मदनपुर खादर क्षेत्र में बसी बस्ती के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में बदतर हालात में जीने को मजबूर हैं। यहां के निवासियों का कहना है कि चुनाव के दौरान नेता वादों की बौछार करते हैं, लेकिन जीतने के बाद उनकी बस्ती की ओर कोई झांकने तक नहीं आता। बस्ती के लोगों को आज भी बिजली और पानी जैसी जरूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

दो दिन बंद रहेंगे ये रास्ते, इंडिया गेट के आस-पास न जाएं, एडवाइजरी देखकर निकलें

परिवहन विशेष न्यूज

गाड़ी चालकों और आम जनता को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी-पॉइंट, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड, मिंटो रोड आदि सहित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली, विजय चौक पर सोमवार और मंगलवार को बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार, विजय चौक सोमवार और मंगलवार को दोपहर 2 बजे से रात 9.30 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। बता दें कि बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है।

विजय चौक पर सोमवार और मंगलवार को बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था के संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार, विजय चौक सोमवार और मंगलवार को दोपहर 2 बजे से रात 9.30 बजे तक सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। बता दें कि बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के औपचारिक समापन का प्रतीक है।

बंद रहेंगे ये मार्ग

एडवाइजरी के मुताबिक रफी मार्ग (सुनहरी मस्जिद के चारों ओर और कृषि भवन के चारों ओर के बीच), रायसीना रोड (कृषि भवन के चारों ओर से विजय चौक की ओर), दारा शिकोह रोड के चारों ओर, कृष्ण मेनन मार्ग के चारों ओर, और सुनहरी मस्जिद के चारों ओर से विजय चौक की ओर तथा कर्तव्य पथ (विजय चौक और 'सी'-हेक्सागन के बीच) पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

इन मार्गों को करें उपयोग

गाड़ी चालकों और आम जनता को रिंग रोड, रिज रोड, अरबिंदो मार्ग, मदरसा टी-पॉइंट, सफदरजंग रोड, कमाल अतातुर्क मार्ग, रानी झांसी रोड, मिंटो रोड आदि सहित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

बस के मुसाफिर दें ध्यान

रिहर्सल को सुविधाजनक बनाने और विजय चौक और इंडिया गेट के आसपास यातायात की भीड़ को कम करने के लिए डीटीसी और अन्य सिटी बसों को सोमवार और मंगलवार को दोपहर 2 बजे से रात 9.30 बजे तक उनके सामान्य मार्गों से हटा दिया जाएगा। शांति पथ, विनय मार्ग-एम, सरदार पटेल मार्ग से आने वाली केंद्रीय सचिवालय और कनॉट प्लेस जाने वाली बसें पंचशील मार्ग, साइमन बोलिवर मार्ग, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड और शेख मुजिलबुर रहमान रोड से होकर जाएंगी। केंद्रीय सचिवालय जाने वाली बसें उद्यान मार्ग पर समाप्त होंगी और काली बाड़ी मार्ग, मंदिर मार्ग और शंकर रोड से वापस आएंगी।

कनॉट प्लेस जाने वाली बसें मंदिर मार्ग, काली बाड़ी मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग से कनॉट प्लेस पहुंचेंगी और भगत सिंह मार्ग, पेशवा रोड, मंदिर मार्ग, शंकर रोड और वंदे मातरम मार्ग से वापस आएंगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और आईएसबीटी कश्मीरी गेट जाने वाली बसें एम्स से रिंग रोड होते हुए धौला कुआं और फिर रिज रोड, रानी झांसी रोड जाएंगी।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, लाल किला और आईएसबीटी कश्मीरी गेट से आश्रम की ओर से आने वाली बसें आश्रम चौक-रिंग रोड से सराय काले खां की ओर जाएंगी और राजघाट होते हुए जाएंगी। कनॉट प्लेस से कस्तूरबा गांधी मार्ग होते हुए इंडिया गेट की ओर आने वाली बसें मिंटो रोड, डीडीयू मार्ग, आईपी फ्लाईओवर, रिंग रोड और सराय काले खां से होकर जाएंगी।

एनसीआरटीसी यात्रियों की दी सौगात, नमो भारत स्टेशन और मेट्रो स्टेशन के बीच फ्री शटल सेवा शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

नमो भारत और मेट्रो स्टेशन के बीच लगभग 300 मीटर की दूरी है। इन दोनों स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए शटल सेवा के तहत ई-रिक्शा उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को पीक आवर्स के दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक निशुल्क पहुंचाएंगे।

नई दिल्ली। एनसीआरटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन और शहीद स्थल, न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन को जोड़ने हेतु निशुल्क शटल सेवा की शुरूआत की है। यह पहल यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में एनसीआरटीसी द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक हिस्सा है।

नमो भारत और मेट्रो स्टेशन के बीच लगभग 300 मीटर की दूरी है। इन दोनों स्टेशनों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए शटल सेवा के तहत ई-रिक्शा उपलब्ध हैं, जो यात्रियों को पीक आवर्स के दौरान एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक निशुल्क पहुंचाएंगे और यात्रियों के लिए आरामदायक, सुरक्षित और परेशानी मुक्त आवागमन सुनिश्चित करेंगे। इसके अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। इस सेवा की मांग बढ़ने पर दोनों स्टेशनों के बीच जारी इस सेवा के बेड़े का विस्तार भी भविष्य मे किया जाएगा।

गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन, गाजियाबाद-मेरठ मार्ग पर मेरठ मोड़ तिराहा पर स्थित है, जो प्रमुख सड़कों के बीच है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पैदल यात्री आवागमन करते हैं। खासतौर पर गाजियाबाद के हजारों निवासी काम और अन्य दैनिक गतिविधियों के लिए मेरठ रोड तिराहा से गुजरते हैं। इसके अलावा, पास में स्थित शहीद स्थल नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन पर भी यात्रियों की आवाजाही काफी होती है। हालांकि, दोनों स्टेशनों के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण यात्रियों को मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए असुरक्षित तरीके से सड़क पार करनी पड़ती है। बढ़ते यातायात को देखते हुए और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को प्राथमिकता देते हुए, एनसीआरटीसी ने इस शटल सेवा की शुरुआत की है।

निकट भविष्य में, शहीद स्थल, न्यू बस अड्डा मेट्रो स्टेशन को फुट-ओवर ब्रिज के माध्यम से नमो भारत स्टेशन से जोड़ा जाएगा, जिससे सुरक्षित और आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। अभी इस फुट-ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस दौरान, यात्रियों के लिए निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए यह शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। एनसीआरटीसी दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की सुविधा के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए फीडर ऑपरेटरों, कैब सेवाओं, ऑटो-रिक्शा और बाइक-टैक्सी प्रदाताओं के साथ सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है।

गाजियाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसें पहले से ही गाजियाबाद के सभी नमो भारत स्टेशनों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान कर रही हैं। ये बसें साहिबाबाद, गाजियाबाद, डीपीएस राजनगर गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नॉर्थ स्टेशनों सहित सात अलग-अलग मार्गों पर चलती हैं। इसके साथ ही मोबिलिटी पार्टनर्स द्वारा टैक्सी सेवाएं भी यात्रियों के लिए उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए छूट भी प्रदान करते हैं।

AAP कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र, दिल्लीवासियों के लिए हो सकते हैं कई बड़े एलान

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) कल यानी सोमवार (27 जनवरी) को अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कल कई बड़ी घाषणाएं कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी अपना घोषणा पत्र तीन पार्ट में जारी कर चुकी है।

दिल्ली में 5 फरवरी को होगा मतदान

बता दें कि राजधानी दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होना है और चुनाव का परिणाम आठ फरवरी को आएगा। वहीं, चुनाव के लिए तीनों प्रमुख पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है।

आप ने भाजपा के संकल्प पत्र पर तीखा हमला बोला

आम आदमी पार्टी ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर रविवार को भी उस पर तीखा हमला बोला है। आप की वरिष्ठ नेता रीना गुप्ता ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र, एक ठग पत्र है। ऐसे ही इन्होंने महाराष्ट्र में भी महिलाओं को ठगा है।

30 लाख महिलाओं से पैसे की वसूली की जाएगी

कहा महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार ने लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं के खाते में पहले पैसे डाले और अब कह रही है कि इनमें से 30 लाख महिलाओं से पैसे की वसूली की जाएगी।

पैसे देकर वापस क्यों लिए जा रहे हैं?

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने के लिए पैसे हैं, लेकिन महिलाओं को देने के लिए नहीं है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं से कहा कि जब भाजपा वाले आएं और 2500 रुपये देने की बात करें तो आप उनसे पूछना कि महाराष्ट्र में महिलाओं को पैसे देकर वापस क्यों लिए जा रहे हैं?

ऐसा कोई संकल्प नहीं है, जिसे भाजपा कभी पूरा करेगी

महाराष्ट्र में तो भाजपा ने महिलाओं को ठग लिया, लेकिन दिल्ली की महिलाएं इनके झांसे में नहीं आएंगी। गुप्ता ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आए और उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का तीसरा भाग दिल्ली की जनता के सामने रखा। इसमें ऐसा कोई संकल्प नहीं है, जिसे भाजपा कभी पूरा करेगी।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखा मेक इन इंडिया का असर

परिवहन विशेष न्यूज

यह विस्तार भारत की महत्वाकांक्षी "मेक इन इंडिया" पहल के साथ सहजता से जुड़ा हुआ है। कंपनियों ने बदलते जमाने की उच्च तकनीक को दिखाया। कंपनियों ने इसके मार्फत अपने विस्तार को दुनिया के अन्य देशों में दिखाया। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने टायर निर्यात मूल्य को 5 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाना और दुनिया भर में शीर्ष तीन टायर उत्पादन केंद्रों में से एक बनना है

नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी एक्सपो में कंपनियों ने मेक इन इंडिया का पूरा असर दिखाई दिया। कंपनियों ने अपने-अपने तरीके से मेक इन इंडिया तकनीक को दिखाया।

टायर निर्माता कंपनी राल्सन टायर्स को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भारतीय कमर्शियल टायर बाजार में प्रवेश की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है। यह रणनीतिक विस्तार राल्सन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि कंपनी साइकिल टायर में अग्रणी होने से ऑटोमोटिव और वाणिज्यिक टायर दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत खिलाड़ी बन गई है।

2023 में इंदौर में अपनी अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा के उद्घाटन के साथ, राल्सन टायर्स भारत में उच्च प्रदर्शन वाले वाणिज्यिक टायरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। 60,000 MTPA क्षमता वाला यह प्लांट, जो वर्तमान में पूरी क्षमता से काम कर रहा है, पहले से ही उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व सहित वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। अब, इस सुविधा की उत्पादन क्षमताएं तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में प्रीमियम वाणिज्यिक टायरों की आपूर्ति के लिए पूरी तरह समर्पित होंगी। यह विस्तार भारत की महत्वाकांक्षी "मेक इन इंडिया" पहल के साथ सहजता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि राल्सन टायर्स देश की टायर निर्माण के लिए एक अग्रणी वैश्विक केंद्र बनने की आकांक्षाओं में अपने योगदान को मजबूत करता है। भारत का लक्ष्य 2030 तक अपने टायर निर्यात मूल्य को 5 बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ाना और दुनिया भर में शीर्ष तीन टायर उत्पादन केंद्रों में से एक बनना है, राल्सन इस दृष्टि को साकार करने में एक अभिन्न भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंदौर सुविधा में निर्मित टायर पहले से ही 50 से अधिक देशों में निर्यात किए जा रहे हैं, जो वैश्विक टायर निर्माण परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को मजबूत करता है। भारतीय वाणिज्यिक टायर बाजार महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है, जो माल ढुलाई की बढ़ती मात्रा, विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे के विकास, मजबूत आर्थिक विकास और उच्च गुणवत्ता वाले रेडियल टायर की ओर बदलाव जैसे कारकों से प्रेरित है। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में बाजार 10% की सीएजीआर से बढ़ेगा, जो राल्सन जैसी कंपनियों के लिए इस बढ़ती मांग को पूरा करने का एक जबरदस्त अवसर पेश करेगा। राल्सन टायर्स के प्रबंध निदेशक श्री मंजुल पाहवा ने कहा, "हम भारतीय बाजार में वाणिज्यिक टायरों की अपनी प्रीमियम रेंज पेश करने को लेकर रोमांचित हैं।" "उत्तरी अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे बाजारों में हमारी वैश्विक सफलता ने हमें ट्रकिंग उद्योग की उभरती जरूरतों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। हम इन उच्च प्रदर्शन वाले टायरों को भारत में लाने के लिए उत्साहित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि स्थानीय परिवहन क्षेत्र को बेहतर गुणवत्ता, बढ़ी हुई ईंधन दक्षता और स्थायित्व से लाभ मिले।" राल्सन के वाणिज्यिक टायर प्रदर्शन, स्थायित्व और ईंधन दक्षता में उत्कृष्टता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। वे बेहतर कर्षण, विस्तारित चलने का जीवन और कम रोलिंग प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए कम परिचालन लागत मिलती है। उन्नत सुविधाएँ सुरक्षा और हैंडलिंग को बढ़ाती हैं, जिससे वे विभिन्न क्षेत्रों में मांग वाले वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। भारत भर में 43 बिक्री और सेवा कार्यालयों के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, राल्सन टायर्स असाधारण ग्राहक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है। कंपनी व्यक्तिगत सेवा प्रदान करके और भारतीय वाणिज्यिक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करके अपने ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने के लिए समर्पित है।

किडनी के मरीज और बाकी सभी के लिए

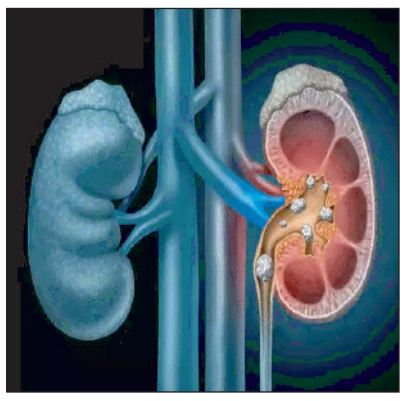

टाक्सिन बाहर तीन तरह से आता है ।

त्वचा के रास्ते पसीने के द्वारा, फेफड़े से सांस के द्वारा और किडनी से पेशाब के द्वारा इन तीनो में 95% टाक्सिन शरीर से बाहर पेशाब के द्वारा ही आता है, इसलिए पानी ज्यादा से ज्यादा पीने की जरुरत है।

लेकिन यदि पेशाब नहीं हो रही है और उसके बावजूद आपने पानी ज्यादा पिया तो जलोदर की प्रॉब्लम हो सकती है।

इसी बात को समझाने के लिए हम यह पोस्ट लिख रहे है I

सबसे पहले इस कड़ी में हमें यह जानना है कि पेशाब बनता कैसे है । हमारी दोनों स्वस्थ्य किडनी 24 घंटे में करीब 450 बार पुरे शरीर के रक्त को फिल्टर करती है इस प्रकार करीब 1700 लिटर खून साफ़ करने का काम किडनी करती है।

दोनों किडनी में करीब 10 लाख से अधिक नेफ्रोंस होते है हर नेफ्रोंस के दो शिरे होते है एक शिरे को ग्लोमेरुँलर और दुसरे शिरे को त्युबुल्स कहते है।

यही हमारे ग्लोमेरुँलर 1700 लिटर खून से 200 लिटर यूरिन बनाते है , जिसका 99% भाग त्युबुल्स एब्जॉर्ब कर लेता है ।और बाकि 1.5 से 2 लिटर यूरिन युरेटर के द्वारा मूत्राशय में जमा होता है।

जब मूत्राशय में करीब 350 एम्एल यूरिन जमा हो जाता है तब हमें पेशाब की अनुभूति होती है I

इसलिए हमेशा जितना पेशाब होता है , उससे 500 एम्एल ज्यादा पानी पीना चाहिए ।

यदि 1.5 लिटर यूरिन हुआ है ।इसका मतलब पेशाब की समस्या नहीं है। और कम से कम 4 से 5 लिटर पानी जरुर पीना चहिये।

अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है , कि जिन्हें पेशाब ठीक से नहीं हो रही है वो पानी की मात्रा कैसे बढ़ाये

इसके लिए उन्हें कुछ घरेलु नुस्खों का प्रयोग करना चाहिए

एलोपैथी दवाओ की मदद से पेशाब को बढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए नहीं तो उससे किडनी पर असर पड़ता है I

कुछ प्रयोग लिख रहे है उसे ध्यान से पढ़िए

मूली के पत्तो का जूस दिन में 4 बजे के पहले एक - एक कप करके 3 बार पी सकते है , इससे यूरिन खुलकर होगा I

हरा धनिया के 50 ग्राम पत्तों को छोटा छोटा काटकर एक गिलास पानी में 10 मिनट उबाले, पत्तों को छानकर फेक दीजिये और पानी को हलका गरम गरम खाली पेट सुबह शाम पीजिये I

सुखा धनिया एक चम्मच एक गिलास गरम पानी में रात भिगो दीजिये और सुबह उसे अच्छी तरह मसलकर धनिया छानकर फेक दीजिये और पानी खाली पेट पीजिये धीरे धीरे पेशाब खुलकर आने लगेगा I

पेशाब नहीं हो रहा है तो एक गिलास गरम पानी में थोडा सा फिटकिरी पाउडर मिलाकर खारा करके पीजिये, इससे पेशाब आने लगेगी, लेकिन जो लोग डायलिसिस करा रहे है वो लोग इस प्रयोग को न करे।

जिन लोगो का पोटैशियम बढा है , वो लोग धनियाँ वाला प्रयोग न करे । उनके लिये मूली के पत्तो वाला प्रयोग सबसे सुरक्षित और सेफ है I

पेशाब में जलन की समस्या

दो छोटी इलायची के दाने दिन में दो बार पानी के साथ निगल लीजिये I

पतली छाछ में सोडा मिलाकर पीजिये I

एक छोटा चम्मच धनिया लें। इसे एक कप बकरी के दूध में मिलाएं, मिठास के लिए मिश्री भी डाल लें। इसे पीने से पेशाब की जलन खत्म होगी I

पानी को अमृत कैसे बनाये

पानी को 20 मिनटस उबालकर सूती कपडे से छानकर ताम्बे के बरतन में या मिटटी के बर्तन में थोड़े से तुलसी के पत्ते डालकर रख दीजिये 3 घंटे के बाद आपका पानी फिर अमृत के जैसा हो जाएगा I

पानी को मिटटी के घड़े में डालकर थोड़ी सी फिटकिरी डालकर रख दीजिये पानी शुद्ध हो जायेगा और उसकी जीवनी शक्ति भी बनी रहेगी I

एक लिटर पानी में 100 ग्राम जौ डालकर 15 मिनट उबालें उसके बाद छानकर रख लीजिये, यह भी पानी बहुत फायदे का रहेगा I

कांच की ग्रीन बोतल में पानी भरकर सूर्य की रोशनी में 8 घंटे के लिए रख दीजिये उसके बाद सुबह सुबह उठाते ही मुह धोकर पीजिये ।एक कप दोपहर के भोजन के आधा घंटा पहले पीजिये एक कप रात का भोजन के पहले पीजिये यह पानी से बचाएगा I

वाटर प्योरिफायर के पानी को मिट्टी के घड़े में रखे फिर 4 घण्टे बाद इस्तेमाल करे।

सोते समय आप भी लेते हैं खर्राटे ?

इन 12 आसान उपायों से दूर हो जाएगी समस्या

मन रखें शांत जिन्हें रात को सोते समय खर्राटे लेने की आदत हो उसे खर्राटे से बचने के लिए रात को सोते समय मन को शांत व मस्तिष्क को बाहरी विचारों से मुक्त रखकर सोना चाहिए।

भरपूर पानी पीएं क्या आप जानते हैं कि शरीर में पानी की कमी से भी खर्राटे आते है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो नाक के रास्ते की नमी सूख जाती है। ऐसे में साइनस हवा की गति को श्वास तंत्र में पहुंचने के बीच में सहयोग नहीं कर पाता और सांस लेना कठिन हो जाता है।

ऐसे में खर्राटे की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिए सेहतमंद और खर्राटों से दूर रहने के लिए दिनभर भरपूर पानी पीएं

वजन कम करें अधिकतर मोटे लोग ही खर्राटों की समस्या के शिकार होते हैं।

गले के आप-पास अधिक वसा युक्त कोशिकाएं जमा होने से गले में सिकुड़न होती है और खर्राटे की ध्वनि निकलती है तो अगर आप भी खर्राटों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपना वजन कम करने के उपाय करें।

करवट से सोएं पीठ के बल सोना वैसे तो आदर्श तरीका होता है लेकिन इस मुद्रा में सोने से खर्राटों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में खर्राटों से बचने के लिए आप अगर करवट के बल सोएंगे तो खर्राटों की आशंका कम होगी।

धूम्रपान से बचें धूम्रपान से खर्राटों की संभावना अधिक होती है। धूम्रपान वायुमार्ग की झिल्ली में परेशानी पैदा करता है और इससे नाक और गले में हवा पास होना रूक जाती है। इसलिए अगर आपको खर्राटों की समस्या हैं तो धूम्रपान छोड़ दें।

नींद की गोलियों से बचें नींद की गोलियों मांसपेशियों पर विपरीत प्रभाव डालती है।

सोने के लिए अगर आप शराब, नींद की गोलियों या अन्य दवाईयों का इस्तेमाल करते है तो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इससे भी खर्राटे आते है।

सोने का समय नियमित रूप से एक ही समय पर सोएं। सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें तथा सोते समय ध्यान रखें कि किसी भी अंग पर जोर न पड़ें।

एक्सरसाइज करें जिस तरह से बॉडी की एक्सरसाइज करने से सारी मांसपेशियां मजबूत होती है।

उसी तरह खर्राटों को कम करने के लिए गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है।

नमक कम खाएं नमक की अधिकता शरीर में ऐसे तरल पदार्थ का निर्माण करता है जिससे नाके के छिद्र में बाधा उत्पन्न होती है और खर्राटे आने लगते है। शोधकर्ता प्रोफेसर जिम हॉर्न के अनुसार, डाइट से नमक कम करके गले की भीतरी सूजन को कम करने में मदद मिलती है जिससे खर्राटे को रोकना आसान हो जाता है।

सिर ऊंचा करके सोएं अगर आपको खर्राटे की समस्या है तो आपको सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा करके सोना चाहिए। ऐसा करने से खर्राटे की समस्या से बचा जा सकता है।

शरीर को पूर्ण आराम सोते समय अपने शरीर को पूर्ण आराम दें तथा सोते समय ध्यान रखें कि किसी भी अंग पर जोर न पड़ें।

भोजन की मात्रा कम लें रात को सोने से पहले ज्यादा भोजन करने से भी खर्राटे की समस्या होती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो सोने से पहले हल्का और कम भोजन करें, साथ ही साथ ही अधिक देर तक जागने से भी बचे।

ड्राई फ्रूट्स

भीगे रखे हुए बादाम, अखरोट, किशमिश, मूंगफली, काले चने, और ब्लूबेरी के साथ नाश्ता स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, यह एक पोषण से भरपूर और स्वादिष्ट संयोजन है। इस नाश्ते में मौजूद तत्व निम्नलिखित फायदों के साथ आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं।।

1 बादाम बादाम में प्रोटीन, फाइबर, और विटामिन ई होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

2 अखरोट अखरोट भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, और विटामिन्स का स्रोत होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ाते हैं।

3 किशमिश किशमिश में आयरन, पोटैशियम, और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो हेल्थी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद होती है।

4 मूंगफली मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर, और विटामिन बी की अच्छी मात्रा होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और ऊर्जा को बढ़ाती है।

5 काले चने काले चने में प्रोटीन, फाइबर, और विटामिन्स की अच्छी मात्रा होती है, जो खासकर वजन नियंत्रण और डाइबिटीज के नियंत्रण में मदद करती है।

6 ब्लूबेरी ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, और फाइबर का अच्छा स्रोत होती है, जो शरीर के लिए उपयोगी होती है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है।

इस तरह का नाश्ता आपको सुबह ऊर्जा और पोषण प्रदान करता है, और आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाए रखने में मदद करता है। मैं इसे अपनी डाइट में रोज़ जोड़कर रखता हूँ आप भी कोशिश कर सकते है

स्वस्थ रहे अच्छे रहे ख़ुश रहे, सभी सुखी और निरोगी रहे

पसली में दर्द के कारण

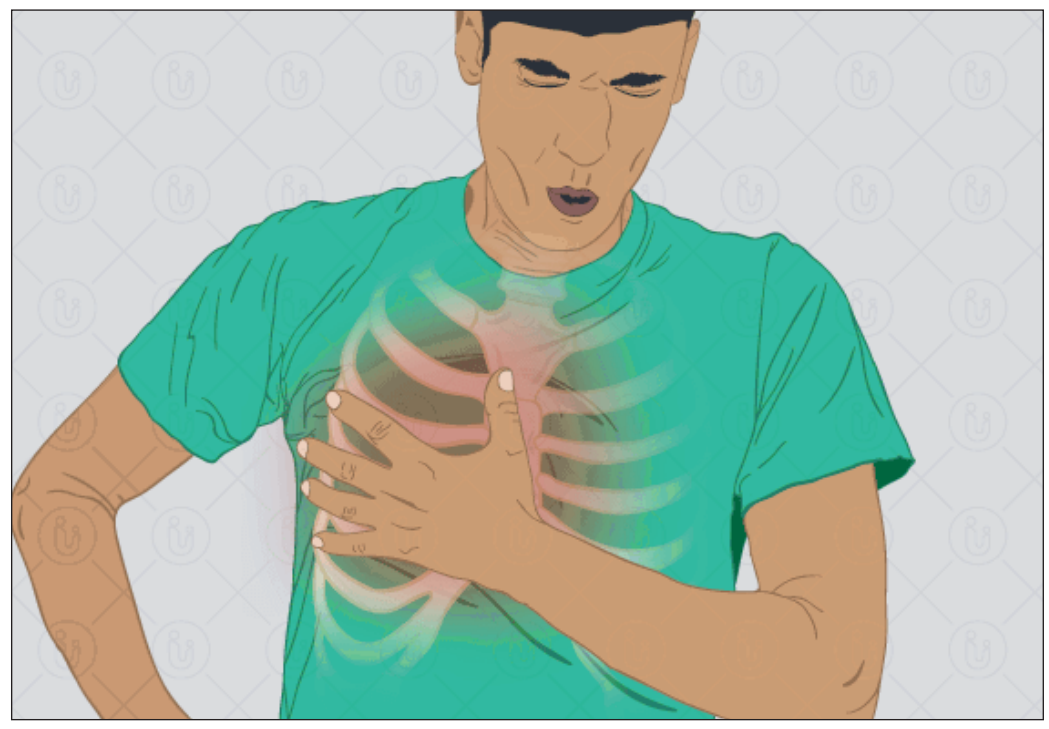

फेफड़ों में कफ जम जाने के कारण नसे जकड़ जाती है जिसके कारण रोगी की पसलियों में दर्द (Pasli me dard)होने लगता है। कभी-कभी जब ठंड लग जाती है तो कफ ऊपर की ओर रुक जाता है, बाहर नहीं आ पाता है जो लोग अधिक गैस पैदा करने वाले पदार्थ खाते हैं। उनको भी यह रोग हो जाता है। यह रोग ठड़ा मौसम और ठडी चीजे खाने से उत्पन्न होता है।

पसली में दर्द के लक्षण

शरीर में वायु के प्रभाव के कारण दर्द शुरू हो जाता है। सबसे अधिक दर्द छाती में होता है। रोगी के माथे पर पसीना आता रहता है जिससे रोगी की बेचैनी बढ़ जाती है।

भोजन तथा परहेज

इस रोग के रोगी को ठंड और ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस रोग में हल्के गर्म तेल की मालिश करें जिससे कि ठंडक दूर होकर रोग में लाभ हो।

पसली में दर्द का आयुर्वेदिक इलाज व घरेलू उपाय

सरसों

20 ग्राम अजवाइन और 5 लहसुन की कलियां (पुती) को 250 मिलीलीटर सरसों का तेल में मिला ले, फिर उसके बाद सरसों के तेल को हल्की आग पर गर्म करें। तेल जब आधा रह जाये तो उसे छानकर शीशी (छोटी बोतल) में भर लें। इस तेल को छाती और पसलियों पर मलने से तुरन्त आराम मिलना है।

पसलियों में दर्द होने पर इन नुस्खों को अजमाएं

एक ग्राम शुद्ध हींग महीन पीसकर सरसो के तेल मे मिलाकर पसली पर लेप करें। आराम मिलेगा।

गेहूं की रोटी एक तरफ सेंक कर दूसरी ओर कच्ची रखें। फिर कच्चे भाग पर सरसों का गर्म तेल मल कर दर्द वाले स्थान पर बांध दें। इससे रोगी को बहुत आराम मिलेगा।

चूना व शहद मिलाकर लेप करने से भी पसलियों के दर्द में आराम मिलता है।

एक ग्लास पानी में 2 चम्मच जीरा डालकर गरम करें। फिर इस गरम पानी में साफ कपड़ा भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ें और उसकी भाप से सेंक करें। रोगी को जल्दी ही आराम मिलेगा।

राई के दानों को महीन पीस कर गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बार बार उसका लेप करें। आराम मिलेगा।

गरम दूध में तीन चार छोटी इलायची पीस कर मिला लें। फिर एक चुटकी हल्दी डालकर रात में सोते समय पिएं। आराम मिलेगा।

सौ ग्राम मेथी दाना हल्का सा भून लें और फिर हल्का सा कूट कर इसमे चौथाई भाग काला नमक मिला लें और सुबह शाम एक-एक चम्मच खाएं। 15-20 दिन खाने से आराम मिलेगा।

सभी सुखी और निरोगी रहे

सर्दियों में अमरूद का जूस पीने के गजब के फायदे

सर्दियों का मौसम है और बाजार में अमरूदों की बहार है ! हरे-भरे अमरूद देखकर लगता है जैसे ये फल कह रहे हों, ₹हमें खाओ, हमें पियो और सेहत बनाओ !₹

अगर आप सोच रहे हैं कि ठंड में क्या हेल्दी पिया जाए, तो जनाब, अमरूद का जूस आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। यह सिर्फ एक जूस नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है। चलिए, जानते हैं क्यों अमरूद का जूस आपके लिए 'सुपरड्रिंक' है।

1 इम्युनिटी का बूस्टर सर्दियों में ठंड और खांसी आपकी नाक पर डेरा डालने के इंतजार में रहती हैं। लेकिन अमरूद का जूस पीते ही आपकी इम्युनिटी कहेगी, ₹अब मैं तैयार हूं !₹ अमरूद में मौजूद विटामिन C आपकी इम्युनिटी को इतना मजबूत बनाता है कि मौसमी बीमारियां आपका पता ढूंढते-ढूंढते थक जाएंगी।

2 पेट का दोस्त, कब्ज का दुश्मन पेट खराब हो तो लाइफ में मजा ही नहीं आता। और कब्ज ? उफ्फ, पूछिए ही मत ! लेकिन अमरूद का जूस आपकी सारी पेट की प्रॉब्लम्स को 'गुडबाय' कह देता है। इसमें मौजूद फाइबर आपके पाचन तंत्र को ऐसा दुरुस्त करता है कि पेट दर्द, गैस और सूजन को दूर भगाने में ये किसी सुपरहीरो से कम नहीं।

3 त्वचा का जादूगर सर्दियों में रूखी त्वचा किसी का भी मूड खराब कर सकती है। लेकिन अमरूद का जूस पीने से आपकी त्वचा इतनी मुलायम और चमकदार हो जाएगी कि लोग पूछेंगे, ₹भाई, ये निखार का राज़ क्या है ?₹ अमरूद आपकी त्वचा को भीतर से पोषण देता है और रूखापन छू-मंतर हो जाता है।

4 वजन कम करने का मास्टरमाइंड, ठंड में हम सबका दिल खाने-पीने में ज्यादा लगता है और वजन चुपचाप बढ़ जाता है। लेकिन अमरूद का जूस एक ऐसा हेल्दी ऑप्शन है, जो आपका वजन कम करने में मदद करता है। इसमें कैलोरी कम होती है, और ये मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देता है कि आपकी वेट-लॉस जर्नी में ये आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है।

5 सर्दियों का सस्ता, टिकाऊ और बहुउपयोगी सुपरफूड, अब आप सोच रहे होंगे, ₹अरे भाई, ये इतना सब करेगा तो महंगा जरूर होगा !₹ लेकिन जनाब, अमरूद ऐसा फल है जो आपके बजट का भी ख्याल रखता है। थोड़े पैसे में आपको हेल्थ, ब्यूटी और फिटनेस का ऐसा पैकेज कहीं और नहीं मिलेगा।

अमरूद का जूस कैसे बनाएं ? अमरूद का जूस बनाना उतना ही आसान है जितना कि इंस्टाग्राम पर रील्स देखना। बस 2-3 पके हुए अमरूद लीजिए, उनके बीज निकालकर मिक्सर में पीस लीजिए। थोड़ा पानी, नींबू का रस और काला नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। लो भई, आपका हेल्दी और टेस्टी जूस तैयार है।

अमरूद का जूस सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि सर्दियों का सबसे बड़ा सुपरहीरो है। इसे अपनी डाइट में शामिल करें और अपनी सेहत को वो ताकत दें, जो इसे वाकई चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं सर्दियों में सेहत और स्वाद का लुत्फ उठाने के लिए ? अमरूद का जूस पिएं और कहें, ₹हेल्थ का सही रास्ता यहीं से जाता है !

सभी सुखी और निरोगी रहे

सोम प्रदोष व्रत

महादेव की पूजा का महत्व हर दिन होता है, लेकिन प्रदोष तिथि की पूजा का खास महत्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा से जीवन में समृद्धि, खुशहाली और भाग्य में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि (13वीं तिथि) को हर महीने होता है। और पूजा का समय प्रदोष काल में होता है।

सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन हिंदू धर्म में भगवान शिव को शक्ति और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष तिथि पर भगवान शिव का अभिषेक (पानी से स्नान) दूध से करने से मन की सारी नकारात्मकता और डर समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रदोष तिथि सोमवार को पड़ जाए। तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। क्योंकि दोनों दिन और अवसर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यधिक शुभ माने जाते हैं।

सोम प्रदोष व्रत की तिथि हिंदू कैलेंडर के अनुसार, माघ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जनवरी 2025 को रात 8:54 बजे शुरू होगी और 27 जनवरी 2025 को रात 8:34 बजे तक समाप्त होगी। इसलिए सोम प्रदोष व्रत 27 जनवरी 2025 को सोमवार को मनाया जाएगा। इस बार माघ मास के खास सोम प्रदोष व्रत की पूजा सोमवार, 27 जनवरी 2025 को होगी।

सोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 27 जनवरी 2025 को भगवान शिव की पूजा का सबसे शुभ समय शाम 5:56 बजे से लेकर 8:34 बजे तक होगा। इस समय के बीच भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए।

सोम प्रदोष शुभ योग इस साल माघ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मूल नक्षत्र रहेगा, जो 9:02 बजे तक रहेगा। और साथ ही हर्षण योग भी बनेगा।

सूर्यः मकर राशि में

चंद्रमाः धनु राशि में

राहु कालः सुबह 8:32 बजे से 9:53 बजे तक

अभिजीत मुहूर्तः दोपहर 12:12 बजे से 12:55 बजे तक

सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि पवित्र स्थान तैयार करें: एक साफ जगह या वेदी पर भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर रखें।

गंगाजल से स्नान कराएं: सबसे पहले भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर को गंगाजल से स्नान कराएं।

चढ़ावे की सामग्रीः अक्षत (अन्न), बेलपत्र (बिल्वपत्र), चंदन, फूल, फल, भांग, शहद, अगरबत्ती और दीपक अर्पित करें।

पंचाक्षर मंत्र का जाप करें: "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का लगातार जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव की स्तुति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें। आरती करें। कपूर या घी के दीपक से भगवान शिव की आरती करें। प्रार्थना करें। पूजा के अंत में अपने परिवार और संतान की सुख-समृद्धि की कामना करें। अगर पूजा में कोई त्रुटि हो, तो भगवान से माफी मांगें। इस पूजा विधि से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है।

सोम प्रदोष व्रत का महत्व क्या है ? सोम प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति की मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। और चंद्रमा से जुड़ी समस्याओं का निवारण भी होता है। यह व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पण का प्रतीक है। और इसे करने से आर्थिक तंगी और रोग दूर होते हैं।

सोम प्रदोष व्रत का पालन कैसे किया जाता है ? सोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसे रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास करना चाहिए। और शाम के समय शिव मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करनी चाहिए। व्रत की विधि और कथा सुनने या पढ़ने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है।

प्रदोष व्रत से कौन-कौन से लाभ होते हैं ? प्रदोष व्रत से इच्छाएं पूर्ण होती हैं, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं, और स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता हैं।

एक बार घर पर बना लें कोरियन चिली पोटैटो बॉल्स, सब बार-बार खाने के लिए मांगेंगे, नोट करें आसान विधि

भारत में इन दिनों कोरियन खाने का ट्रेंड खूब बढ़ गया है। आजकल सोशल मीडिया पर भी कोरियन खाने की रेसिपीज वायरल होती रहती हैं। कोरियन स्पाइसी नूडल्स को ज्यादातर लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये खाने में काफी अलग और बेहद टेस्टी है। यदि आप ने भी कोरियन डिशेज नहीं खाई हैं, तो आप घर आसानी से कोरियन चिली पोटैटो बॉल्स बना सकते हैं। इसे बनाना काफी आसान है, चलिए आपको रेसिपी बताते हैं।

कोरियन चिली पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए आपको चाहिए-

- चार उबले मसले हुए आलू
- चार बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर
- एक बड़ा चम्मच तेल
- चार से पांच लहसुन की कटी हुई कलियां
- दो बड़े चम्मच सोया सॉस
- एक बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया
- आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
- आधा छोटा चम्मच सफेद तिल
- एक से डेढ लीटर पानी

कैसे बनाएं कोरियन चिली पोटैटो बॉल्स

इसे बनाने के लिए चिली पोटैटो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले कुछ आलू लें और इसे अच्छे से धो लें। फिर इन आलू को अच्छे से उबाल लीजिए। उबालने के बाद इन आलू को मसले लें। अब 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा मसले आलू में डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिलाएं। आलू का आटा आपका तैयार है। इस आटे का छोटा-छोटा हिस्सा लें और बॉल्स तैयार कर लें। अब एक पैन में एक लीटर पानी और एक बड़ा चम्मच तेल डालें और इसमें आलू के बॉल्स डालें। फिर इसे कम से कम 10 मिनट तक उबालें। अब इन उबले आलू में धनिया पत्ती. चार लहसुव की कटी हुई कलियां, जो बड़े चम्मच सोया सॉस, आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सफेद तिल और आधा कप गर्म तेल डालें। सभी को अच्छे से मिलाएं और कोरियाई चिली पोटैटो बॉल्स का मजा लें।

दिल्ली-NCR में कई कोचिंग सेंटर अचानक क्यों हुए बंद? विवादों से घिरे FIITJEE ने दी सफाई

परिवहन विशेष न्यूज

फिटजी के कई सेंटरों पर ताला लगने से छात्रों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया है। संस्थान का कहना है कि यह समस्या अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। हालांकि अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। फिटजी ने साजिश की आशंका भी जताई है और छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देने की बात कही है।

नई दिल्ली, विवादों से घिरे फिटजी (FIITJEE) का पूरे मामले पर स्पष्टीकरण सामने आया है। फिटजी की तरफ से जारी बयान से इसके छात्रों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। कोचिंग संस्थान ने कहा है कि यह समस्या अस्थायी है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। उसने आश्वस्त किया है छात्रों की पढ़ाई और उनके भविष्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

13 प्वाइंट में जारी बयान में संस्थान ने कहा कि उसने अपने स्तर पर किसी सेंटर को बंद करने का फैसला नहीं लिया है। सेंटर के मैनेजमेंट साझीदार और उनकी टीम के अचानक पीछे हटने से किसी सेंटर ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। कंपनी के अधिकारी सभी स्थानों पर परिचालन को फिर से शुरू करने में जुटे हैं।

FIITJEE ने जताई साजिश की आशंका

अभी तक दुर्भावनापूर्णवश केस दर्ज हुए हैं, उन पर हमारी कानूनी टीम काम कर रही है। कंपनी को इसमें साजिश की भी आशंका है। उसका कहना है कि जांच में यह सामने आ जाएगा कि कुछ लोगों ने यह षडयंत्र रचा है। सच हमेशा के लिए नहीं छिप सकता। हम अनुचित तरीके अपनाने वाले अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया से भी अनुरोध किया है कि वह सच को सामने लाए। कंपनी ने अपने सभी छात्रों से भरोसा बनाए रखने का आह्वान किया है।

फिटजी का ग्रेटर नोएडा सेंटर बंद, एमडी समेत चार नामजद

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-तीन में छात्र-छात्राओं को एकेडमिक और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने वाला फिटजी कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया। प्रबंधन के लोग बिना सूचना 21 जनवरी को सेंटर पर ताला लगाकर फरार हो गए। अभिभावकों को फोन पर सेंटर बंद का मैसेज मिला तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अभिभावक और छात्र-छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।

क्या बोले अभिभावक?

नॉलेज पार्क थाने में अभिभावक मनोज सिंह की शिकायत पर एमडी डीके गोयल, सीएफओ राजीव बब्बर, मनीष आनंद, ग्रेनो शाखा का हेड रमेश बटलेश व अन्य के खिलाफ मुकदमा हुआ है। उन्होंने शिकायत दी कि फिटजी सेंटर में 125 से ज्यादा छात्र-छात्राएं पढ़ते थे। बेटी सुहाना 11वी कक्षा की छात्रा है।

जेईई एडवांस की पढ़ाई के लिए वर्ष 2022 में उसका दाखिला करा दिया। चार वर्षीय पाठ्यक्रम की दो लाख 90 हजार रुपये फीस बताई गई। उन्होंने चैक से 2.80 लाख रुपये जमा किए। 2026 में उसका कोर्स पूरा होना था, लेकिन 21 जनवरी को फोन पर अचानक मैसेज आया कि फिटजी सेंटर के अध्यापक संस्थान छोड़कर चले गए हैं।

अब छात्र-छात्राओं को पढ़ाई कराने की व्यवस्था नहीं है। सेंटर को बंद कर दिया गया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि फिटजी के प्रबंधन ने पढ़ाई के बहाने लाखों रुपये जमा कर धोखाधड़ी की है। इससे सैंकड़ो बच्चों का भविष्य संकट में होने से सभी मानसिक रूप से परेशान हैं। उच्च अधिकारियों ने मामले की जांच उपनिरीक्षक मुरारी लाल को दी है।

पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे कई अभिभावक

सेंटर बंद सूचना के बाद कई अभिभावकों ने थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की। वे इतने गुस्से में थे कि कोई जल्दी से बात नहीं समझ रहा था।

एसीपी ने अभिभावकों को समझाकर मामले से संबंधित दस्तावेज और अपने बयान रिकार्ड कराने के लिए कहा। संस्थान में पढ़ाने वाले पूर्व शिक्षकों का कहना है कि उन्हें करीब वर्ष से सैलरी मिलने में दिक्कत हो रही थी। इस वजह से सभी ने दूसरे सेंटर में छात्र-छात्राओं को पढ़ाना शुरू कर दिया है।

नोएडा सेक्टर-58 थाने में भी हो चुका है मुकदमा दर्ज

सेक्टर-62 में फिट्जी सेंटर बंद होने के बाद शुक्रवार को सेक्टर-58 थाना पुलिस ने मैनेजिंग डायरेक्टर डीके गोयल, संस्थान प्रभारी रमेश बटलेश, मोनिका गोयल, पार्थ हल्दर, साधू राम बंसल, रूस्तम दिनशां बाटलीवाला, शशिकांत दूबे, मोहित सरदाना, आनंद रमन पी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था।

अभिभावकों ने सेंटर पर हंगामा और प्रदर्शन किया था। यहां सेंटर में दो हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं पढ़ते थे। प्रबंधन ने 21 जनवरी तक क्लासेस लीं और तय समय से एक घंटा पहले छुट्टी कर दी थी।

पुलिस अधिकारी का बयान

एसीपी अवनीश दीक्षित का कहना है कि अभिभावक मनोज सिंह ने फिटजी के एमडी डीके गोयल, सीएफओ राजीव बब्बर, सीईओ मनीष आनंद व ग्रेटर नोएडा ब्रांच के हेड रमेश बटलेश व अन्य पर जालसाजी, धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था।

शिकायत पर चार नामजद और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विवेचक को हर पहलू पर जांच के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

ब्लड कैंसर के मरीज पर सफदरजंग हॉस्पिटल में पहली बार हुई टी-कोशिका थेरेपी

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

VMMC और सफदरजंग अस्पताल ने प्रो. संदीप बंसल (चिकित्सा अधीक्षक) के नेतृत्व में अपनी पहली चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर (CAR) टी-सेल थेरेपी सफलतापूर्वक की है, जो कुछ खास तरह के लिम्फोमा और रक्त कैंसर के लिए एक नया उपचार है। सफदरजंग अस्पताल द्वारा जारी बयान के अनुसार, ₹यह महत्वपूर्ण उपलब्धि विभागाध्यक्ष डॉ. कौशल कालरा के नेतृत्व में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के समर्पण और विशेषज्ञता से संभव हुई है।₹

CAR-T सेल थेरेपी एक उन्नत इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर से लड़ने के लिए रोगी की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं, विशेष रूप से टी-कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करती है। टी-कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया जाता है ताकि वे शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की तुलना में कैंसर कोशिकाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित और नष्ट कर सकें। यह उपचार नॉन-हॉजकिन लिंफोमा जैसे कैंसर के रोगियों के लिए एक गेम-चेंजर साबित हुआ है, खासकर

उन लोगों के लिए जो दुर्दम्य या पुनरावर्ती बीमारी से पीड़ित हैं, जो पारंपरिक उपचारों का जवाब नहीं देते हैं। बयान में कहा गया है, ₹सफदरजंग अस्पताल में पहली CAR-T थेरेपी एक ऐसे रोगी को दी गई थी, जिसे दुर्दम्य नॉन-हॉजकिन लिंफोमा का निदान किया गया था, जो रक्त कैंसर का एक प्रकार है जो पारंपरिक उपचारों का विरोध करता है।₹ डॉ. कौशल कालरा ने कहा, ₹रोगी ने उपचार को अच्छी तरह से सहन किया है, जो रोगी और चिकित्सा टीम दोनों के लिए एक उत्साहजनक परिणाम है। यह सफल मामला अत्याधुनिक कैंसर देखभाल प्रदान करने के अस्पताल के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि के साथ, सफदरजंग अस्पताल भारत में पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया है, जो CAR-T सेल थेरेपी प्रदान करता है, जो एक अत्यधिक विशिष्ट और परिष्कृत उपचार विकल्प है।₹ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. संदीप बंसल ने इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह देश भर के रोगियों को उन्नत चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए संस्थान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। डॉ. संदीप ने कहा, 'उत्तर भारत में केवल दो अन्य सरकारी संस्थानों - पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली - ने सीएआर-टी सेल थेरेपी की है, जिससे सफदरजंग अस्पताल इम्यूनोथेरेपी के बढ़ते क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। यह उपलब्धि न केवल सफदरजंग अस्पताल की एक अग्रणी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में स्थिति को बढ़ाती है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में रोगियों के लिए इस जीवन रक्षक उपचार तक पहुंच का विस्तार भी करती है।'

प्रवेश वर्मा का बड़ा आरोप, बोले- केजरीवाल बंटवा रहे 500-500 रुपये, कैलेंडर में छिपाकर दिए गए नोट

प्रवेश वर्मा ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग दोनों से की है। इसमें उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गया है। अब नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आप के राष्ट्रीय संयोजन अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविवार को प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल वोट के बदले नोट बांट रहे हैं।

कैलेंडर में डालकर दिए 500 रुपये

वर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप के कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली विधानसभा इलाके की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घरों में कैलेंडर में 500-500 रुपये के नोट डालकर दिए हैं। इसका एक वीडियो संजय कैंप से सामने आया था। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन्होंने बताया कि ये सभी 800 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं।

चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से की शिकायत

प्रवेश वर्मा ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग दोनों से की है। इसमें उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। साथ ही इस गिरोह का भंड़ाफोड़ करने की मांग की है। फिलहाल इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई सफाई नहीं आई है।

बढ़ी प्रवेश की मुश्किल

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पंजाबी लोगों की दिल्ली में घूम रही गाड़ियों को लेकर सुरक्षा संबंधी बयान देने वाले भाजपा नेता प्रवेश शर्मा के खिलाफ रविंदर सिंह ने बठिंडा अदालत में मानहानि का केस दायर किया है। इस मामले में 28 जनवरी को सुनवाई होगी। इसके चलते एक बार फिर से भाजपा को विपक्षी दलों के विरोध का सामना करना पड़ रहा।

'केजरीवाल है नटवरलाल, दिल्ली को किया बर्बाद', शिवराज सिंह का 'आप' पर तीखा हमला

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली चुनावके मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान ने करावल नगर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने AAP पर जमकर हमला बोला और अरविंद केजरीवाल को नटवरलाल करार दिया। चौहान ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया है और प्रदूषण दिया है। उन्होंने दिल्ली वालों को पानी नहीं दिया और शराब की नदियां बहा दीं। चौहान ने कहा भाजपा का एलान है भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।

नई दिल्ली, दिल्ली में करावल नगर में जनसभा में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा मामा को करावल नगर वालों ने बुलाया और मामा देखो चले आए।

दिल्ली को कर दिया बर्बाद

शिवराज सिंह ने कहा कि राम हर किसी के रोम-रोम में बसे हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा व प्रदूषण दिया। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को पानी नहीं दिया। दिल्ली में शराब की नदियां बहा दीं। अरविंद केजरीवाल नटवरलाल है, उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया।

ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं, जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। केजरीवाल देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। कहा था सत्ता में आने पर बंगला नहीं लेंगे।

लेकिन सत्ता में आते ही बंगला व गाड़ी दोनों ली। अपने लिए शीशमहल बनवा लिया। भाजपा वाले केजरीवाल को गालियां नहीं देते हैं। उन्हें आम लोग गालियां देते हैं।

यमुना में छठ मनाने से केजरीवाल ने रोका

शिवराज सिंह ने कहा प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। बताओं यमुना में कोई डुबकी लगा पा रहा है। पर्वांचल के लोगों को यमुना में छठ मनाने से केजरीवाल ने रोका। केरजीवाल के गले में हाथ डालकर जनता का पैसा निकाल लेंगे। भाजपा का एलान है कि भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।

दिल्ली में अंधेरा छाटना है तो भाजपा को लाना होगा

उन्होंने कहा बेटियों के नाम पर संपत्ति नाम करवाने पर भाजपा ने छूट दी। केजरीवाल दिल्ली की बहनों को धोखा दे रहे हैं। शिवराज सिंह ने कहा 'एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बंटोगे तो कटोगे।' दिल्ली में अंधेरा छाटना है तो भाजपा को लाना होगा। आठ फरवरी को दिल्ली केजरीवाल से फ्री हो जाएगी।

'लोकतंत्र का ही कमाल, जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनीं', अमित शाह की जनसभा में 'बंटेंगे तो कटेंगे' के जमकर लगे नारे

Delhi Election 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नरेला के रामदेव चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा में एक हैं तो सेफ हैं बंटेंगे तो कटेंगे के जमकर नारे लगे। वहीं इस दौरान भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आगे विस्तार से पढ़िए अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए क्या-क्या कहा है।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज (शनिवार) को नरेला के रामदेव चौक पर एक जनसभा को संबोधित किया। वहीं, अमित शाह के अभिवादन के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं।

बता दें कि जनसभा में 'एक हैं तो सेफ हैं', बंटेंगे तो कटेंगे' के जमकर नारे लगे। इस दौरान भाजपा समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आज 76वां गणतंत्र दिवस है। इन 75 वर्षों में हमारे देश के लोकतंत्र की जड़े पाताल से भी गहरी ले जाने का कार्य जनता ने ही किया। लोकतंत्र का ही कमाल है कि एक चायवाला नरेंद्र मोदी पीएम तीसरी बार बना। यह संविधान का ही कमाल है कि एक गरीब आदिवासी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनीं। एक सामान्य जाट समाज का बेटा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने।

डबल इंजन की सरकारें विकास की गाथाएं लिख रही

अमित शाह ने कहा आठ फरवरी को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी। केजरीवाल के कुशासन का अंत आठ फरवरी को आएगा। मैं आज बताने आया हूं। नरेला, बांकनेर, होलंबी कलां जैसे वार्ड केजरीवाल की राह देख रहे हैं कि कब पांच साल आए और केजरीवाल को हटाए। दस साल के केजरीवाल के शासन के अंदर दिल्ली बद से बदतर हो गई। दस साल में जहां डबल इंजन की सरकारें विकास की गाथाएं लिख रही हैं। लेकिन दस साल में दिल्ली से गंदगी खत्म नहीं हुई और स्कूल खत्म हो गए। अस्पताल में सुविधाओं का नामों निशान नहीं है।

24 घंटे स्वच्छ पानी पीने को मिलता है क्या?

आप सभी के वार्ड में कूड़ा समय पर उठता है क्या? 24 घंटे स्वच्छ पानी पीने को मिलता है क्या? स्कूलों की हालात ठीक है क्या? मोहल्ला क्लीनिक काम में आते हैं क्या? हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देशभर में जाकर अपने पसीने की महक से देश को आगे बढ़ाया है। उसको अपमानित करने का काम केजरीवाल ने किया। बिहार, उत्तर प्रदेश वालों को क्या दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल ने कोरोना के दौरान पूर्वांचलियों को भगाने का कार्य किया है।

मोहल्ला क्लीनिक का झुनझुना पकड़ाया

शाह ने कहा केजरीवाल सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है। 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम भाजपा सरकार करेगी। केजरीवाल सरकार गरीबों को आयुष्मान भारत से दूर रखने का कार्य आप पार्टी ने किया। मोहल्ला क्लीनिक का झुनझुना पकड़ाया। मोतियाबिंद, किड़नी का इलाज मोहल्ला क्लीनिक में नहीं होता है।

यमुना में डुबकी लगाने से बीमार हो गए

देशभर में गरीबों को पांच लाख तक का इलाज मुफ्त मिलता है, लेकिन केजरीवाल के शासन ने 10 साल का नुकसान कर दिया। हम सूद समेत दस लाख का इलाज करा देंगे। यमुना को शुद्ध करने की बात केजरीवाल ने कही। छठ पूजा करने जो जाते हैं वो बताए कि क्या यमुना में डुबकी लगा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे यमुना में डुबकी लगाने से बीमार हो गए। कल कटआउट को डुबकी लगवाई वह भी बीमार हो गया है।

केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन में अन्ना के साथ आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे। लेकिन दल बना दिया। फिर कांग्रेस का समर्थन न लेने की बात कही तो कांग्रेस का समर्थन ले लिया। फिर गाड़ी, बंगला और सुरक्षा नहीं लेने की बात कही। लेकिन 51 करोड़ का शीशमहल बना लिया।

केजरीवाल ने चार बंगले तोड़कर एक बंगला बनाने का काम किया। छह करोड़ के मार्बल, 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख रुपये के लगे हैं। 50 लाख की कालीन बिछाई गई। 10 लाख के सोफे लगाए गए। मैंने केजरीवाल को कहा लेकिन, वह मेरी मानते नहीं है। मैंने कहा था कि दिल्ली वालों को शीशमहल में चाय पिला दो ताकि वह देख लें। लेकिन नहीं किया। टैंकर माफिया से दिल्ली को मुक्त बनाने, फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाने की बात कही थी लेकिन, आपदा ने नहीं किया। झूठ बोलेने के लिए ही केजरीवाल ने जन्म लिया। केजरीवाल के घोटालों की सूची इतनी बड़ी है कि यह सूची एक सप्ताह में भी पूरी नहीं होगी।

मैं आज मोदी की गारंटी को कहने को आया हूं। भाजपा सरकार बनते ही पांच तारीख से पहले 2500 रुपये महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे। 10 लाख रुपये तक का सारा इलाज मुफ्त में करने का भाजपा सरकार करेगी। आठ फरवरी से तीन साल में यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम किया जाएगा। गरीबों को पांच रुपये खाने की थाली की व्यवस्था करेंगे। ऑटो वालों का बीमा करेंगे। 1700 अनधिकृत कॉलोनियों को पूरा मालिकाना अधिकार देने का काम भाजपा करेगी। 13 हजार दुकानों फ्री होल्ड करेंगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को फ्री होल्ड संपत्ति देने का काम करेंगे। भाजपा को जिता दो, दो साल में दिल्ली को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुक्त कर देंगे।

मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं। हमने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। फरवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर बनाया। मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने का कार्य किया है। केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। दस साल हो गए मोदी जी के शासन में बम धमाके बंद हो गए हैं। 31 मार्च 2026 से देश से नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मोदी जी काम सिविल कोड लेकर आए हैं। देश की अर्थव्यवस्था पांचवे नंबर पर हैं। दो साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की बन जाएगी।

कम्युनिटी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और सफलता हासिल करने में मदद करने के लिहाज से साझेदारी अहम

साझेदारियां कई लिहाज से अहम होती है मसलन यह साझेदारी ट्रक ड्राइवरों को 'चालक से मालिक' बनाने के ट्रक्स अप के मिशन को मजबूत बनाएगी तथा ट्रक मालिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। इस तरह छोटे फ्लीट मालिक कारोबार का स्मार्ट फैसला ले सकेंगे अपनी संचालन दक्षता में सुधार ला सकेंगे आसान फाइनैंस पाकर उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेंगे।

नई दिल्ली। मौजूदा समय में कम्युनिटी को आर्थिक रुप से सशक्त बनाने के लिए और कारोबार में सफलता हासिल करने के लिहाज से साझेदारी सबसे अहम है।

इसी के मद्देनजर ट्रक्स अप ने सैकण्ड हैण्ड ट्रकों के लिए आसान, किफ़ायती और निर्बाध फाइनैंसिंग समाधान उपलब्ध कराने के लिए एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य छोटे फ्लीट मालिकों को प्रतिस्पर्धी ब्याज़ दरों पर कम ईएमआई के लोन उपलब्ध कराकर उन्हें सहयोग प्रदान करना है। इससे सैकण्ड हैण्ड ट्रक खरीदने वालों को रीफाइनैंस के आसान विकल्प मिलेंगे और वे अपनी फाइनैंशियल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आसानी से टॉप-अप लोन पा सकेंगे। यह पहल ट्रक ड्राइवरों के कारोबार को बढ़ाने के लिए उनकी पूंजी संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में योगदान देगी।

यह साझेदारी ट्रक ड्राइवरों को 'चालक से मालिक' बनाने के ट्रक्स अप के मिशन को मजबूत बनाएगी तथा ट्रक मालिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। इस तरह छोटे फ्लीट मालिक कारोबार का स्मार्ट फैसला ले सकेंगे, अपनी संचालन दक्षता में सुधार ला सकेंगे, आसान फाइनैंस पाकर उद्यमी बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकेंगे।

इस साझेदारी पर बात करते हुए वीरेन्द्र यदुवंशी, सीईओ, ट्रक्सअप ने कहा, ''हमें खुशी है कि भारत में ट्रक ड्राइवरों को सशक्त बनाने के हमारे लक्ष्य में सहयोग प्रदान करने के लिए एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक हमारे सामरिक साझेदार के रूप में हमारे साथ जुड़ गया है। एयू स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड ट्रक चालकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर लोन देकर उनकी पूंजी संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मैं आभारी हूं, जिन्होंने हमारे काम पर भरोसा किया और हमारे मिशन को समझना, उनके मूल्य हमारे मूल्यों से मेल खाते हैं। यह साझेदारी भारत में ट्रक मालिकों के अनुभव को बदल देगी, और वे सफल कारोबार बनाकर अपने सपने साकार कर सकेंगे।'

वाहिद रज़ा, वाईस प्रेज़ीडेन्ट, वैल्यू-एडेड सर्विसेज़, ट्रक्सअप ने इस साझेदारी पर बात करते हुए कहा, ''हमें खुशी है कि हमें इस बैंक जैसा मजबूत पार्टनर मिला है, जो हमारे लक्ष्य को साझा करता है।

गुरुग्राम में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ चोरी और लूट के पांच आरोपी को धर दबोचा

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम क्राइम न्यूज़ पांच आरोपितों को क्राइम ब्रांच की सेक्टर-39 टीम ने मुठभेड़ के बाद सेक्टर-56 थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपितों के पैर में गोली लगी है। उनके कब्जे से एक सीएनजी ऑटो एक पिस्टल दो कट्टे पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए। लेख के माध्यम से पढ़िए कि इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है।

गुरुग्राम। चोरी एवं लूट की वारदातों को अंजाम देने के पांच आरोपितों को क्राइम ब्रांच की सेक्टर-39 टीम ने मुठभेड़ के बाद सेक्टर-56 थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपितों के पैर में गोली लगी है। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

आरोपितों की पहचान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नंगला मेव गांव निवासी होशियार खान एवं बिलादिन उर्फ बिल्ला, नूंह जिले के घासेड़ा गांव निवासी शाहरूख, खोरी शाह चोखा गांव निवासी मोहम्मद नसीम एवं सलीम उर्फ शमी के रूप में की गई। होशियार एवं बिलादिन फिलहाल नूंह की नायब गली में रह रहे थे। उनके कब्जे से एक सीएनजी आटो, एक पिस्टल, दो कट्टे, पांच जिंदा कारतूस बरामद किए गए।

बृहस्पतिवार देर रात क्राइम ब्रांच की सेक्टर-39 टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर विश्व गौरव को सूचना मिली कि एक बिना नंबर प्लेट के सीएनजी आटो रिक्शा में सवार होकर चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले चार-पांच युवक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ आ रहे हैं। उनके पास अवैध हथियार भी हैं।

इसके बाद तत्काल प्रभाव से एक टीम गठित कर मौके लिए रवाना किया गया। घाटा गांव के नजदीक नाकेबंदी की गई। कुछ देर बाद बिना नंबर प्लेट का ऑटो रिक्शा नाके की तरफ आता हुआ दिया। जब टीम ने चालक को रोकने का इशारा किया तो उसने स्पीड बढ़ाकर भागने का प्रयास किया और बैरिकेड में टक्कर मारते हुए आगे पुलिस की गाड़ी में भी टक्कर मार दी।

इसके बाद आटो रिक्शा से पांच युवक उतरकर टीम पर गोली चलाते हुए जंगल की तरफ भागने लगे। एक गोली इंस्पेक्टर विश्व गौरव की बुलेट प्रूफ जैकेट पर तथा एक गोली पुलिस की गाड़ी की खिड़की में लगी। पुलिस ने कई बार आत्मसमर्पण करने के लिए लेकिन वे गोली चलाते रहे।

फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की। एक-एक गोली दो युवकों के पैर में लगी। इससे वे गिर गए। इसके बाद सभी को काबू कर लिया गया। पकड़े गए आरोपितों में से होशियार एवं बिलादिन को गोली लगी है।

अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। तीन अन्य से पूछताछ जारी है। फिंगरप्रिंट टीमों को सूचना से अवगत करवाकर घटनास्थल का निरीक्षण करा लिया गया है। इंस्पेक्टर विश्व गौरव ने बताया कि मुठभेड़ कि दौरान कुल आठ राउंड फायर हुए। जिनमें से आरोपियों की तरफ चार एवं पुलिस की तरफ से भी चार राउंड फायर किए गए।

प्रारंभिक पूछताछ के मुताबिक आरोपित बिलादिन पर चोरी करने, चोरी का सामान छिपाने, उत्तर-प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत पांच मामले उत्तर प्रदेश में तथा आरोपित होशियार खान पर चोरी करने, चोरी का सामान छुपाने तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत चार मामले उत्तर प्रदेश में अंकित हैं।

गुरुग्राम में सीवर ओवरफ्लो होने से स्कूल के सामने भरा गंदी पानी, गणतंत्र दिवस मनाने पहुंचे बच्चे हुए परेशान

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम के बेगमपुर खटोला गांव में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर सीवर का पानी भर गया है। इस सीवर के पानी में से ही बच्चों को स्कूल आना जाना पड़ रहा है। रविवार को गणतंत्र दिवस मनाने स्कूल पहुंचे बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्र-छात्राओं का कहना है कि पिछले काफी दिनों से सीवर ओवरफ्लो से समस्या हो रही है।

बादशाहपुर। नगर निगम गुरुग्राम की लापरवाही गांव के निवासियों के साथ-साथ स्कूली बच्चों पर भी भारी पड़ रही है। नगर निगम की लापरवाही से गांव की सड़क नदी की तरह लग रही है। सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रहा है।

गांव के राजकीय वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और राजकीय प्राथमिक संस्कृति मॉडल स्कूल के बच्चों को स्कूल में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए नगर निगम की लापरवाही से बनी इस नदी को पार करके जाना पड़ रहा है।

काफी दिनों से समस्या से जूझ रहे लोग

ऐसा नहीं है कि यह समस्या केवल एक दिन ही हुई है। ग्रामीणों को पिछले काफी दिनों से इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने नगर निगम के छोटे से बड़े सभी अधिकारियों से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह कर लिया।

नगर निगम के अधिकारी इस समस्या का ठीकरा गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के सिर फोड़ रहा है। जबकि जीएमडीए के अधिकारी इस समस्या के लिए नगर निगम गुरुग्राम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लापरवाही नगर निगम गुरुग्राम की हो या जीएमडीए की बेगमपुर खटोला की जनता को इस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है।

शिकायत के बावजूद नहीं सुन रहे अधिकारी

बेगमपुर खटोला आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष श्रवण राजपूत का कहना है कि पिछले तीन-चार साल से सीवर लाइन ओवरफ्लो होने की समस्या आ रही है। नगर निगम गुरुग्राम के छोटे से बड़े सभी अधिकारियों को शिकायत कर ली कोई भी समाधान करने को तैयार नहीं है।

नगर निगम गुरुग्राम के जेई कपिल इस समस्या के लिए जीएमडीए को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जेई से बात करते हैं तो वह कहता है कि जीएमडीए का एसटीपी ठीक से काम न करने के कारण सीवर का पानी वापस आकर ओवरफ्लो होता है। जीएमडीए के एसडीओ सुरेंद्र कौशिक से बात की तो उन्होंने बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी रोजाना खाली किया जाता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।

गांव के पूर्व सरपंच बसंत राघव कहते हैं कि नगर निगम गुरुग्राम के अधिकारियों को आमजन की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। जब भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या बढ़ती है। जेई कपिल आकर लीपा-पोती कर देते हैं। एसडीओ या बड़े अधिकारियों को लोगों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है।

गांव के योगेश चौहान, नरेंद्र पंवार, गौतम तंवर का कहना है कि उनका गांव नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड-26 में आता है। वार्ड-26 के नगर निगम के एसडीओ आशीष हुड्डा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है।

उनके स्थान पर किसी सिविल के इंजीनियर को बतौर एसडीओ नियुक्त किया जाए ताकि वह इस समस्या को देख सके और गांव वालों को समस्या का समाधान दे सके।

क्या बोले निगम आयुक्त ?

नगर निगम गुरुग्राम के निगम आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बेगमपुर खटोला गांव में सीवर ओवरफ्लो की समस्या के समाधान के लिए वार्ड-26 के एसडीओ और जेई को साथ लेकर संयुक्त आयुक्त को दौरा करने के निर्देश दिए हैं। संयुक्त आयुक्त पूरी समस्या को देखकर ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान कराएंगे।

एप के जरिये थार बुक कर गबन करते थे शातिर, पुलिस के हत्थे चढ़े तीन बदमाश

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा पुलिस ने जूम ऐप के जरिए कार बुक कर गबन करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से गबन की थार कार भी बरामद हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित पहले भी इसी तरह किराये पर वाहन बुक कर गबन कर चुके हैं।

ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने जूम एप के माध्यम से कार बुक कर गबन करने वाले शातिर गिरोह के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से गबन की थार कार को भी बरामद कर लिया है।

पहले भी ऐसा कर चुके हैं आरोपी

आरोपितों की पहचान बलवीर नगर शाहदरा दिल्ली के प्रशांत ठाकुर, गांव पाली बमरोली थाना श्याना बुलंदशहर के विनय सिरोही व सेलाकुओ देहरादून के जतिन के रूप में हुई है। पुलिस जांच में शामिल आया है कि शातिर बदमाश पहले भी इसी तरह किराये पर वाहन बुक कर गबन कर चुके हैं।

जूम ऐप से किराये पर देते थे कार

24 जनवरी को ईकोविलेज एक सोसायटी की टावर संख्या बी-पांच के फ्लैट संख्या 106 के रहने वाले अक्षय शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने बताया था कि उसके पास थार कार उनकी पत्नी सलोनी पांडेय के नाम पंजीकृत है।

कार को जूम ऐप के माध्यम से किराये पर कार देने का व्यवसाय करते हैं। 23 जनवरी को ऐप के माध्यम से सूर्यकांत नाम के एक शख्स ने बुक किया था। जिसके बाद एक युवक आया।

शक होने पर पीड़ित ने पुलिस की दी जानकारी

उसने अपना नाम जतिन बताया वह कार को लेकर चला गया। जिसके बाद आरोपितों ने कार को वापस नहीं किया। शक होने पर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कर जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया।

पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि गिरोह में शामिल बदमाश इसी तरीके से किराये पर लेकर पहले भी कारों को हड़प चुके हैं। पुलिस ने शनिवार को तीनों आरोपितों को कार समेत दबोच लिया। आरोपित कार में सवार होकर एटीएस गोलचक्कर से चार मूर्ति की तरफ जा रहे थे।

18 सौ रुपये में दो घटे के लिए बुक की थी थार

पुलिस पूछताछ में आरोपित जतिन व विनय सिरोही ने बताया कि उन्होंने अपने साथी सूर्यकांत का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सिम कार्ड का प्रयोग कर बिना उसकी जानकारी के 23 जनवरी को जूम ऐप के जरिए दो घटे के लिए 18 सौ रुपये में बुक की थी।

बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल पुलिस

सूर्यकांत का आधार कार्ड दिखाकर कार को लेकर चले गए थे। कार ले जाकर उन्होंने प्रशांत ठाकुर के साथ मिलकर उसे बेचने की कोशिश की। प्रशांत ठाकुर भी गिरोह के सदस्यों में शामिल है। पुलिस बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है।

भ्रष्टाचार की जड़-कर्मचारी, मंत्री द्वारा थर्ड पार्टी से की गई मिलीभगत व सांठगांठ, शासन से की गई गद्दारी धोखाधड़ी है

आओ मिलीभगत छोड़ सत्य निष्ठा ईमानदारी से अपने पद की जवाबदेही निभाने की शपथ लें
शासकीय कर्मचारी, मंत्री का पद और कुर्सी उसकी रोजी-रोटी का साधन है, मिलीभगत सांठगांठ कर पाए भ्रष्टाचार का फ़ल उन्हें जरूर मिलेगा-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भ्रष्टाचार शब्द सदियों से चला आ रहा है।भारत में तो यह सैकड़ों साल पूर्व अंग्रेजों के ज़माने से ही चला रहा है, परंतु अब इस शब्द के साथ एक नई थीम मिलीभगत व साठगांठ जुड़ गई है जो हमें अब कई बार सुनाई देता है कि सब मिलीभगत है और कुछ नहीं। कई न्यायालयों से भी कमेंट आता है कि आप उसकी मदद ही नहीं कर रहे हैं, आपकी उसके साथ मिलीभगत है। अनेक बार अनेक राज्यों में कई पुल गिर जाते हैं या भयानक हादसों में भी टीवी चैनलों पर जो बयान आते हैं उसमें अनेक खामियों को देखते हुए वहां भी मिलीभगत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है दिनांक 25 जनवरी 2025 को मिली भगत के चलते ही श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे योशिता राजपक्षे को शनिवार को पुलिस ने संपत्ति खरीद मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया इसलिए आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से भ्रष्टाचार में मिलीभगत और उसे तोड़ने के लिए हम चर्चा करेंगे भ्रष्टाचार की जड़-कर्मचारी मंत्री द्वारा थर्ड पार्टी से की गई मिलीभगत व सांठगांठ, शासन से की गई गद्दारी धोखाधड़ी है।

साथियों बात अगर हम प्रैक्टिकली अनेक शासकीय विभागों में उनके कार्यालयों में देखें तो हमें बाबू से लेकर बड़े अधिकारियों द्वारा चकरें खिलाए जाते हैं कुछ अपवाद छोड़ दें तो यह स्थिति करीब-करीब हर कार्यालय में देखने को मिलती है, इसलिए हमारे दिमाग में बात आती है सब मिलीभगत है, क्योंकि हम अगर वही काम किसी बिचौलिए या दलाल के थ्रू करने जाते हैं तो नीचे से ऊपर तक का काम हाथों-हाथ हो जाता है इसीलिए हम फिर सोचते हैं कि यह मिलीभगत नहीं तो फिर क्या है? खास करके शासकीय कार्यालयों का मुझे निजी अनुभव है कि कैसे मिलीभगत काम होता है।

साथियों बात अगर हम हर पद पर बैठे बाबू से लेकर उच्च अधिकारी की करें तो उन्हें हर वर्क को केंद्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से हर कार्यालय द्वारा जागरूकता सप्ताह बनाकर सत्य निष्ठा और ईमानदारी की शपथ दिलाई जाती है और करीब - करीब हर कार्यालय अपने कर्मचारियों अधिकारियों को शपथ दिलाता है अगर वास्तव में इन कर्मचारियों द्वारा शपथ का पालन किया जाता है तो मिली भगत का नाम ही नहीं आएगा क्योंकि जब भ्रष्टाचारी नहीं होगा तो मिलीभगत यानें नीचे से ऊपर तक की चेन ही टूट जाएगी इसके लिए हर स्तर के अधिकारी बाबू चपरासी से लेकर मंत्री तक को यह शपथ लेनी होगी और सभी शासकीय कार्यों को सभी पहलुओं में सत्य निष्ठा पारदर्शिता और सुशासन के उच्चतममानकों को बनाए रखने के लिए सटीक नेतृत्व हर कार्यालय के प्रमुख को करना होगा।

साथियों बात अगर हम मिलीभगत की करें तो यह अधिकतम शासकीय मामलों भ्रष्टाचार और राजनीतिक क्षेत्रों में अधिक सुनने को मिलता है मेरा मानना है कि पद आसीन बाबू से लेकर अधिकारी को अपना माइंडसेट इस सत्य निष्ठा से करना होगा कि यह पद रूपी अन्नदाता हमारी रोजी-रोटी प्रदान करता है इसके साथ गद्दारी मंजूर नहीं इसका संकल्प तो हम हर वर्ष जागरूकता सप्ताह मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परंतु जरूरत है इसे निष्पादन करने की वैसे अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया कॉन्टेंट-मिलीभगत दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक कपटपूर्ण समझौता या गुप्त सहयोग है जो दूसरों को उनके कानूनी अधिकार को धोखा देकर, गुमराह करने या धोखा देकर खुली प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है। मिलीभगत को हमेशा अवैध नहीं माना जाता है। क्योंकि तकनीकी रूप से, अगर हम विभिन्न आपराधिक विधियों की खोज करेंगे, तो हमें मिलीभगत शब्द नहीं मिलेगा लेकिन सांठ गांठ करना और कानून को तोड़ना भी संभव है।

साथियों बात अगर हम मिलीभगत सांठगांठ से भ्रष्टाचार के कनेक्शन की करें तो, व्यावसायिक धोखाधड़ी एक कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान शासन के साथ की गई धोखाधड़ी है। वे अधिक आम हैं और तीसरे पक्ष द्वारा की गई धोखाधड़ी की तुलना में शासन को अधिक वित्तीय नुकसान पहुंचाते हैं।चूंकि कर्मचारी शासन में काम करना जारी रखेंगे, इसलिए वे आम तौर पर इन धोखाधड़ी को स्थायी रूप से छिपाने की कोशिश करेंगे, जिसका अर्थ है कि शासकीय धोखाधड़ी लंबे समय तक की जा सकती है। मिलीभगत और रिश्वतखोरी योजनाएं क्या हैं?, यह वह स्थिति है जब कोई कर्मचारी किसी अन्य पक्ष (चाहे वह शासन के बाहर से हो या अंदर से) के साथ मिलकर कर्मचारी के रूप में अपनी भूमिका का उपयोग करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करता है। मिलीभगत से धोखाधड़ी शासन की पुस्तकों से बाहर होती है। यानी, आमतौर पर शासन के रिकॉर्ड में किसी भी गतिविधि को छिपाने की आवश्यकता नहीं होती है।सबसे आम तौर पर ज्ञात मिलीभगत धोखाधड़ी रिश्वतखोरी है - किसी विशिष्ट कार्य को प्रभावित करने के लिए दी गई कोई चीज़ - चाहे किसी कार्य के किए जाने के बाद दी गई हो या भविष्य में कोई लाभ या जानकारी प्राप्त करने के लिए दी गई हो। मिलीभगत भी हितों के टकराव की धोखाधड़ी हो सकती है। हालाँकि इन धोखाधड़ी में ज़रूरी नहीं कि कोई अलग तीसरा पक्ष शामिल हो, लेकिन वे कर्मचारी को कर्मचारी के अलावा किसी अन्य भूमिका में शामिल करेंगे

साथियों बात अगर हम मिलीभगत और सांठगांठ को प्रैक्टिकल वे में देखने की कोशिश करें तो, रिश्वतखोरी धोखाधड़ी (1) बोली या टेंडर में हेराफेरी (2) रिश्वत या गुप्त कमीशन, रिश्वत का इस्तेमाल भ्रष्ट कर्मचारी के हस्तक्षेप के माध्यम से दूसरों पर अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रिश्वत किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रभाव के बदले में किसी अन्य पक्ष द्वारा निर्णयकर्ता या निर्णय प्रभावित करने वाले को मूल्यवान वस्तु देना है। रिश्वत और निर्दोष वाणिज्यिक विपणन के बीच एक ग्रे क्षेत्र है। किसी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने या विपणन करने का प्रयास कहाँ रिश्वत बन जाता है? व्यावहारिक उत्तर यह है कि क्या शासन को व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित लाभ प्राप्त करने के बारे में जानकारी है और क्या उसने इसके लिए स्वीकृति दी है। शासन की जानकारी और सहमति के बिना, संभावना है कि किसी कर्मचारी द्वारा लाभ प्राप्त करना रिश्वत के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर का दूसरा भाग यह है कि क्या लाभ किसी विशिष्ट निर्णय को सीधे प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा है या समग्र संबंध बनाए रखने के लिए। मिलीभगत सांठ गांठ से रिश्वतखोरी कैसे की जाती है। बेईमान कर्मचारी रिश्वत देने वाले से रिश्वत लेता है। आम तौर पर पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मूल्यवान कोई भी चीज़ (उपहार, मनोरंजन, कर्मचारी या उनके रिश्तेदारों के लिए छुट्टियाँ, बिलों का भुगतान, यौन एहसान आदि) रिश्वत के रूप में दी जा सकती है। फिर रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाले को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। रिश्वतखोरी के तीन मुख्य प्रकार हैं: (ए) ओवर- बिलिंग योजनाएं- ओवर- बिलिंग योजनाएँ आमतौर पर खरीद अनुबंधों से संबंधित होती हैं। कर्मचारी को उस आपूर्तिकर्ता को दूसरों पर वरीयता देने के लिए रिश्वत दी जाती है। आपूर्ति की गई वस्तुएँ या सेवाएँ या तो उनकी कीमत से अधिक हो सकती हैं, या अपेक्षा से कम गुणवत्ता वाली हो सकती हैं। खरीद अनुबंध में अन्य छिपी हुई लागतें, शुल्क या उच्च मूल्य भिन्नताएँ भी हो सकती हैं। वास्तव में, व्यवसाय आपूर्ति के लिए बहुत अधिक भुगतान करता है, और यह अधिक मूल्य निर्धारण रिश्वत से कमाया गया लाभ है। (बी) कम कीमत वाली योजनाएं-अंडर-प्राइसिंग स्कीम ओवर-बिलिंग स्कीम के विपरीत हैं। इनमें आमतौर पर व्यवसाय द्वारा पार्टियों को सामान और सेवाएँ ऐसी कीमतों पर बेची जाती हैं जो सामान्य रूप से दी जाने वाली कीमतों से कम या कम अनुकूल शर्तों पर होती हैं। खरीदार को लाभ यह होता है कि उन्हें बेहतर सौदा मिलता है, जिसके वे अन्यथा हकदार होते। इस मामले में व्यवसाय को अपने उत्पाद या सेवा के लिए बहुत कम प्रतिफल मिलता है क्योंकि वे कम कीमत पर बेचे जाते हैं, और लागत बचत रिश्वत से होने वाला लाभ है।(ग) अनुबंध, पदोन्नति आदि प्रदान करना-इन योजनाओं में ऐसी शर्तों पर अनुबंध प्रदान करना शामिल है जो व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल नहीं हैं। वे अधिक लागत पर हो सकते हैं, कम गुणवत्ता वाली सामग्री शामिल कर सकते हैं और / या ऐसी शर्तें हो सकती हैं जो नियोक्ता के लिए सबसे अनुकूल नहीं हैं। इसमें व्यवसाय के भीतर कर्मचारियों को पदोन्नति देना भी शामिल है - जहां रिश्वत देने वाले को अन्य अधिक योग्य लोगों से ऊपर पदोन्नत किया जाता है - या अनुपयुक्त कर्मचारियों को काम पर रखा जाता है। सीखने योग्य सबक-(1) सभी नुकसान संसाधनों की चोरी से नहीं होते। भ्रष्ट कर्मचारी द्वारा किए गए कपटपूर्ण निर्णयों से भी शासन को नुकसान हो सकता है। (2) मिलीभगत से की गई धोखाधड़ी में रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने वाले किसी भी लेनदेन को हटाया या छिपाया नहीं जाता। केवल अकाउंटिंग रिकॉर्ड की जांच करके इस तरह की धोखाधड़ी का पता लगाने की संभावना बहुत कम है। (3) मिलीभगत की योजनाएं शासन चक्र के किसी भी क्षेत्र पर हमला कर सकती हैं, जहां कोई कर्मचारी बाहरी पक्षों के साथ लेन-देन करता है, लेकिन इसमें केवल शासन के भीतर के कर्मचारी और आंतरिक लेनदेन ही शामिल हो सकते हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भ्रष्टाचार की जड़-कर्मचारी, मंत्री द्वारा थर्ड पार्टी से की गई मिली भगत व सांठगांठ, शासन से की गई गद्दारी धोखाधड़ी हैआओ मिलीभगत छोड़ सत्य निष्ठा ईमानदारी से अपने पद की जवाबदेही निभाने की शपथ लें

शासकीय कर्मचारी, मंत्री का पद और कुर्सी उसकी रोजी-रोटी का साधन है, मिलीभगत सांठगांठ कर पाए भ्रष्टाचार का फ़ल उन्हें जरूर मिलेगा

दिल्ली में मुफ्त चुनावी उपहारों के शोर में असल मुद्दे दब कर रह गये हैं

आम आदमी पार्टी ने मुफ्त योजनाओं की जो आदत जनता को लगाई है उसको देखते हुए अन्य पार्टियां भी इसी नीति पर चलती नजर आ रही हैं। यह नीति राजनीतिक दलों को सत्ता तो दिला देगी लेकिन सरकारी खजाने को और राज्य की आर्थिक सेहत को खासा नुकसान पहुँचाएगी।

अक्सर आपने देखा होगा कि किसी राज्य में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक और सामाजिक समीकरण हावी हो जाते हैं लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में हालात एकदम अलग हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक चर्चा में ''मुफ्त उपहारों'' की चर्चा हावी है जिससे प्रदूषण, कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ अपराध और बुनियादी ढांचा सहित अन्य प्रमुख मुद्दे पीछे रह गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के लिए निःशुल्क सार्वजनिक परिवहन पहल पर जोर देते हुए ''रेवड़ी पर चर्चा'' जैसे अभियानों का नेतृत्व कर रही है। इसने नयी योजनाओं की भी घोषणा की है, जिनमें महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये देने के वादे के साथ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और बुजुर्गों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी संजीवनी योजना शामिल है।

कांग्रेस ने जवाब में 'प्यारी दीदी योजना' की घोषणा की है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने की बात कही गई है। इसने 25 लाख रुपये तक की बीमा कवरेज का वादा करते हुए 'जीवन रक्षा योजना' की घोषणा भी की है। वहीं भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र के दो चरण अब तक जारी किये हैं जिनमें हर वर्ग के लिए योजनाओं की भरमार है। देखा जाये तो इन मुफ्त योजनाओं को एक बार 'मुफ्त की रेवड़ी' करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना पड़ा है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो इस तरह की योजनाएं जारी रखी जाएंगी।

इस बीच, मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त उपहारों की घोषणाओं के चलते दिल्ली में वायु प्रदूषण जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा गौण हो गया है। हालांकि राजधानी के ज्यादातर निवासियों ने गंभीर स्वास्थ्य खतरा बने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कार्य योजनाओं की कमी पर चिंता जताई है। हम आपको बता दें कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) पिछले साल नवंबर में 490 के अंक को पार कर गया, जो ''अत्यंत गंभीर'' श्रेणी में आता है। जहरीली हवा के कारण अनेक लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, यमुना नदी में अमोनिया के उच्च स्तर के कारण पूरे शहर में पानी की कमी भी देखी गई क्योंकि जलशोधन संयंत्र पानी का शोधन करने में असमर्थ थे। यही नहीं, खराब जल निकासी के चलते दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में तीन यूपीएससी अभ्यर्थियों की डूबने से मौत को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में आक्रोश देखा गया था।

बहरहाल, देखा जाये तो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से शासन एवं नीति-निर्माण पंगु हो गये हैं। अपने अब तक के कार्यकाल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोजगार सृजन और संविदा कर्मचारियों के लिए समाधान खोजने जैसे अन्य प्रमुख मुद्दों की अनदेखी की है। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त योजनाओं की जो आदत जनता को लगाई है उसको देखते हुए अन्य पार्टियां भी इसी नीति पर चलती नजर आ रही हैं। यह नीति राजनीतिक दलों को सत्ता तो दिला देगी लेकिन सरकारी खजाने को और राज्य की आर्थिक सेहत को खासा नुकसान पहुँचाएगी। यहां सवाल यह भी उठता है कि हम 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं लेकिन जब देश की राजधानी ही विकसित नहीं होगी तो यह लक्ष्य आखिर कैसे हासिल होगा?

बैटरी, रेंज, फीचर्स और कीमत के मामले में कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी को खरीदना होगा बेहतर

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा बीई 6 बनाम टाटा कर्वव्ी ईवी महिंद्रा की ओर से Auto Expo 2025 में अपनी नई Electric SUV के तौर पर Mahindra BE 6 को लॉन्च किया गया है। कंपनी की ओर से लाई गई इस ईवी का सीधा मुकाबला Tata Curvv EV के साथ होगा। Battery Range Features और Price के मामले में दोनों में कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी को खरीदना बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में Electric SUVs की मांग लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए वाहन निर्माताओं की ओर से भी कई एसयूवी को पेश और लॉन्च किया जा रहा है। Auto Expo 2025 में Mahindra की ओर से BE 6 की कीमतों की घोषणा की गई है। बाजार में इसका मुकाबला Tata Curvv EV के साथ होगा। डिजाइन, Features, Range, Battery, Price के मामले में किस Electric SUV को खरीदना बेहतर (Mahindra BE 6 Vs Tata Curvv EV) हो सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Mahindra BE6 Vs Tata Curvv Battery and Range

महिंद्रा की ओर से BE6 को Electric SUV सेगमेंट में लॉन्च किया गया है। जिसे दो बैटरी पैक के विकल्प के साथ लाया गया है। इसके बेस वेरिएंट Pack One में कंपनी की ओर से 59 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाता है। जिससे इसे सिंगल चार्ज में 557 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसमें लगी मोटर से इसे 179 किलोवाट की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसमें रीजनरेशन के चार लेवल भी मिलते हैं जिससे रेंज को बढ़ाने में मदद मिलती है।

वहीं Tata Curvv EV में 45 kWh और 55kWh की क्षमता की बैटरी के विकल्प दिए गए हैं। जिसमें लॉन्ग रेंज वेरिएंट को फुल चार्ज में ARAI 585 किलोमीटर की रेंज (tata curvv ev range) मिलती है। वहीं 45 kWh बैटरी के साथ इसे 502 किलोमीटर की ARAI रेंज मिलती है। 70kW चार्जर से सिर्फ 40 मिनट में 10 से 80 फीसदी चार्ज किया जा सकता है। सिर्फ 15 मिनट में एसयूवी को 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है।

Mahindra BE 6 Vs Tata Curvv Features

महिंद्रा की BE 6 में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। इसमें बाई-एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, 12.3 इंच की दो स्क्रीन दी जाती हैं जिसमें से एक का उपयोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरे का उपयोग इंफोटेनमेंट सिस्टम के तौर पर किया जाता है। इसके साथ ही इसमें एलईडी डीआरएल, टर्न इंडीकेटर, 18 इंच अलॉय व्हील्स, छह स्पीकर ऑडियो सिस्टम, ओटीए अपडेट, वायरलेस एंड्राइड ऑटो, एपल कार प्ले, पुश बटन स्टार्ट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील्स, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, मल्टी ड्राइव मोड्स, ऑटो एसी, ऑटो हेडलैंप, ऑटो वाइपर, कंसोल कूलिंग स्टोरेज जैसे फीचर्स को दिया जाता है।

वहीं Tata Curvv EV में 18 इंच व्हील्स के अलावा 450 एमएम वाटर वेडिंग कैपेसिटी, फ्लश डोर हैंडल, कनेक्टिड एप, एलईडी लाइट्स, वेंटिलेटिड सीट्स, मल्टी ड्राइव मोड्स, एंबिएंट लाइट, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट के साथ जेस्टर एक्टीवेशन, क्रूज कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, कूल्ड ग्लोव बॉक्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Mahindra BE 6 Vs Tata Curvv Price

महिंद्रा की ओर से BE 6 को 18.90 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 26.90 लाख रुपये है।

वहीं Tata Curvv EV के बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 17.49 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट को 21.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

अमेरिका, रूस जैसे देशों के प्रमुख किन कारों में करते हैं सफर, किस तरह की होती हैं खूबियां

परिवहन विशेष न्यूज

विश्व सूची की आधिकारिक राज्य कारें भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दौरान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बेहद सुरक्षित कारों में सफर करते हुए नजर आते हैं। दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल अमेरिका रूस चीन ब्रि टेन के राष्ट्र प्रमुख किन कारों में सफर करते हैं और उनमें सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत सहित दुनियाभर के राष्ट्र प्रमुख सबसे सुरक्षित कारों में सफर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और पीएम के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन जैसे ताकतवर देशों के प्रमुख किस तरह की कार में सफर (Official State Cars of World) करते हैं। इनमें सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए (Presidential Cars) जाते हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

भारत के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार है Mercedes Benz S 600

भारत के राष्ट्रपति के लिए जिस गाड़ी का उपयोग किया जाता है वह तकनीक के साथ ही सुरक्षा के मामले में भी काफी बेहतरीन कार है। जर्मनी की वाहन निर्माता Mercedes Benz की ओर से Maybech S600 Pullman Gaurd को ऑफर किया जाता है। जिसे चलता हुआ किला कहा जा सकता है। इसमें बुलेट प्रूफ अलॉय व्हील्स, टायर्स, प्रिवेंटिव शील्ड, ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ही VR9 स्तर की सुरक्षा को दिया जाता है। जिससे इस पर मिलिट्री राइफल शॉट्स, गैस अटैक, बम और अन्य किसी भी तरह के धमाके का असर नहीं होता।

भारत के प्रधानमंत्री करते हैं इस गाड़ी में सफर

भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम की आधिकारिक कार के तौर पर फिलहाल Range Rover Sentinal का उपयोग किया जाता है। इस गाड़ी को भी राष्ट्रपति की गाड़ी की तरह ही काफी सुरक्षित बनाया गया है। यह गाड़ी AK-47 जैसे ताकतवर हथियार के हमले से भी अंदर बैठे सवारों को सुरक्षित रख सकती है। इसके अलावा पीएम के काफिले में Mercedes Benz Maybech S650 जैसी बेहद सुरक्षित गाड़ी भी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं इस गाड़ी का उपयोग

दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति भी काफी सुरक्षित गाड़ी का उपयोग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उपयोग की जाने वाली कैडिलेक लिमोजिन को The Beast नाम से भी जाना जाता है। इस गाड़ी में सैन्य स्तर का आर्मर उपयोग किया जाता है जो पांच इंच तक मोटा होता है। इसके दरवाजे भी आठ इंच मोटे होते हैं और यह किसी भी तरह के हथियार के अलावा केमिकल हमले तक को झेल सकती है। इसमें राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप के दो बैग को भी रखा जाता है, जिससे जरुरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है।

चीन के राष्ट्रपति करते हैं इस गाड़ी का उपयोग

चीन के राष्ट्रपति भी बेहद खास गाड़ी का उपयोग सफर के लिए करते हैं। उनके पास होंगकी 701 नाम की गाड़ी है जो बुलेटप्रूफ कार है। इस कार को रेड फ्लेग भी कहा जाता है और इस पर किसी भी तरह के हथियार के साथ ही रसायनिक हमले का भी असर नहीं होता।

रूस के राष्ट्रपति करते हैं इस गाड़ी का उपयोग

रूस भी दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल है। इसके राष्ट्रपति के लिए आधिकारिक तौर पर ऑरस सीनेट (Aurus Senat) लिमोजिन कार को उपयोग किया जाता है। जिनसे मर्सिडीज एस600 पुलमैन गार्ड की जगह ली है। इसे भी संघीय सुरक्षा सेवा के मानकों के मुताबिक ही बनाया गया है। इस कार पर भी किसी भी तरह के हथियार के हमले का असर नहीं होता।

हीरो एक्सपल्स 210 भारत में 2 वेरिएंट में हुई लॉन्च, फीचर्स के मामले में एक-दूसरे से कितनी अलग

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्सपो में हीरो एक्सपल्स 210 वेरिएंट के बारे में बताया गया 2025 में हीरो मोटोकॉर्प ने Hero XPulse 210 को लॉन्च किया। इसे दो वेरिएंट बेस और टॉप मॉडल में लेकर आया गया है। इन दोनों की कीमतों में 10 हजार रुपये का फर्क भी है। इसके साथ ही टॉप वेरिएंट में बेस वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं। बाकी इंजन दोनों में एक ही लगाया गया है।

नई दिल्ली। Bharat Mobility Global Expo 2025 में हीरो मोटोकॉर्प ने XPulse 210 को लॉन्च किया था। इसे दो वेरिएंट में लाया गया है, जो बेस और टॉप मॉडल है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 1,75,800 रुपये, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 1,85,800 रुपये है। जिस तरह से इनकी कीमत में 10 हजार रुपये का फर्क है उसी तरह से इनमें फीचर्स का भी काफी अंतर है। आइए जानते हैं कि XPulse 210 के बेस और टॉप मॉडल में कितना अंतर है।

डिजाइन

XPulse 210 के दोनों वेरिएंट को एक जैसा ही डिजाइन दिया गया है, इनमें बस थोड़ा सा ही अंतर बै। इसके बेस वेरिएंट को दो कलर ऑप्शन में लाया गया है, जो वाइल्ड रेड और ग्लेशियर व्हाइट है। इसके टॉप वेरिएंट को भी दो कलर स्कीम दिया गया है, जो एज़्योर ब्लू और अल्पाइन सिल्वर है। यह दोनों ही अलग-अलग शेड्स के साथ आते हैं। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में बेहतर विंड प्रोटेक्शन के लिए लंबी विंडस्क्रीन दी गई है, जबकि बेस वेरिएंट में छोटी फ्लाईस्क्रीन है।

फीचर्स

XPulse 210 को दोनों वेरिएंट के बीच उनमें दिए गए फीचर्स में है। इसके टॉप वेरिएंट में TFT डिस्प्ले दिया गया है, जबकि बेस वेरिएंट में LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल किया गया है।

टॉप वेरिएंट में तीन राइडिंग मोड रोड, ऑफ रोड और रैली के साथ डुअल-चैनल ABS भी दिया गया है, जबकि बेस वेरिएंट में कोई ड्राइविंग मोड नहीं दिया गया है इसमें केवल सिंगल-चैनल ABS है।

इसके टॉप वेरिएंट में नक्कल गार्ड और पीछे की तरफ लगेज माउंटिंग प्लेट दिया गया है, जबकि XPulse 210 बेस वेरिएंट में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है।

डाइमेंशन

XPulse 210 के बेस वेरिएंट 168 किलोग्राम का है, जबकि टॉप वेरिएंट का वजन 170 किलोग्राम है। इसके दोनों वेरिएंट में 210 मिमी ट्रैवल वाला टेलिस्कोपिक फोर्क, 205 मिमी ट्रैवल वाला 10-स्टेप प्री-लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक और दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक दिया गया है। इनकी सीट की ऊंचाई 830 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 220 मिमी है।

इंजन

हीरो XPulse 210 के दोनों वेरिएंट में ही 210cc सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह इंजन 24.6 PS की पावर और 20.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को छह-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ जोड़ा गया है।

मारुति से लेकर टाटा तक ने पेश और लॉन्च की ये बेहतरीन इलेक्ट्रिक एसयूवी, कीमत भी 30 लाख रुपये से कम

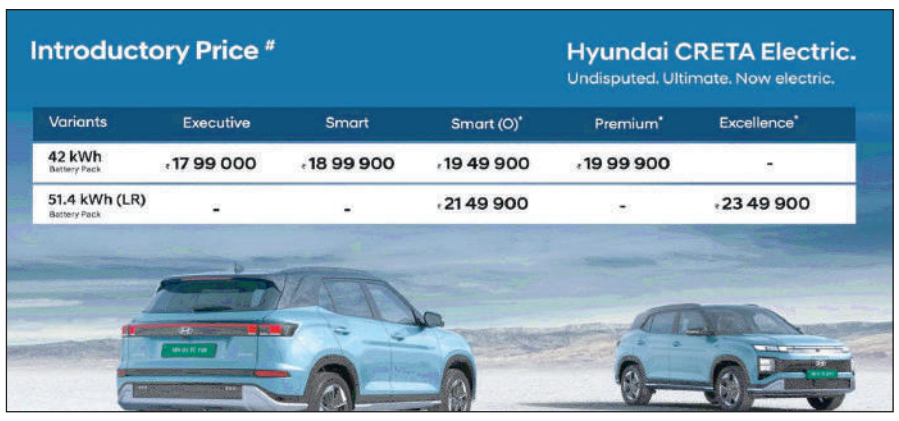

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्सपो में इलेक्ट्रिक एसयूवी 2025 भारत में 17 से 22 जनवरी 2025 के बीच Bharat Mobility 2025 के तहत Auto Expo 2025 का आयोजन किया गया था। इस दौरान देश और दुनिया की कई वाहन निर्माताओं की ओर से Electric SUVs को पेश और लॉन्च किया। 30 लाख रुपये से कम कीमत में कौन सी इलेक्ट्रिक एसयूवी को पेश और लॉन्च किया गया। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी 2025 के तहत दिल्ली एनसीआर में आयोजित किए गए Auto Expo 2025 में कई बेहतरीन वाहनों को पेश और लॉन्च किया गया। कई निर्माताओं की ओर से Electric SUV सेगमेंट में भी कई उत्पादों को पेश और लॉन्च किया गया। इस दौरान 30 लाख रुपये तक की कौन सी Electric SUVs को पेश और लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti E Vitara हुई पेश

भारत की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान अपनी पहली Electric SUV के तौर पर Maruti E Vitara को पेश किया गया। जिसे अगले कुछ महीनों के दौरान औपचारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से इसमें दो बैटरी पैक के विकल्प दिए जाएंगे जिससे इसे 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिल पाएगी। लॉन्च के समय ही कीमतों की घोषणा की जाएगी।

Hyundai Creta Electric

साउथ कोरियाई वाहन निर्माता हुंडई की ओर से क्रेटा के इलेक्ट्रिक वर्जन को ऑटो एक्सपो 2025 में लॉन्च किया गया। इस गाड़ी को 17.99 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर लाया गया है। इसमें भी दो बैटरी पैक के विकल्प दिए गए हैं जिससे अधिकतम 473 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है।

Mahindra BE 6

महिंद्रा की ओर से 2024 के आखिरी में BE 6 को Electric SUV के तौर पर पेश किया गया था। जिसे Auto Expo 2025 में लॉन्च किया गया। कंपनी की ओर से इस एसयूवी की एक्स शोरूम कीमत 18.90 लाख रुपये से लेकर 26.90 लाख रुपये के बीच रखी गई है।

Mahindra XEV 9e

महिंद्रा की ओर से एक और Electric SUV के तौर पर Auto Expo 2025 में XEV 9e को लॉन्च किया गया। इस एसयूवी को 21.90 लाख रुपये से लेकर 30.50 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के बीच लाया गया है। इसे सिंगल चार्ज में 656 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

Tata Sierra

टाटा की ओर से Auto Expo 2025 के दौरान Tata Sierra को भी पेश किया गया। कंपनी की ओर से जल्द ही इसके Electric वर्जन को लाया जा सकता है। इसमें भी बैटरी पैक के कई विकल्प दिए जा सकते हैं और इसकी अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर के आस-पास हो सकती है।

Tata Harrier EV

टाटा की ओर से Auto Expo 2025 में Tata Harrier EV को भी शोकेस किया गया था। इसे कंपनी ऑल व्हील ड्राइव के साथ लाएगी। जिसे सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर तक की रेंज को दिया जा सकता है। इसकी संभावित एक्स शोरूम कीमत 25 लाख रुपये के आस-पास हो सकती है।

Vinfast VF3

वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता Vinfast ने भी Auto Expo 2025 से भारत में अपने सफर को शुरू किया है। कंपनी की ओर से दो ईवी को पेश किया गया है। लेकिन इसके साथ ही कई और इलेक्ट्रिक एसयूवी को शोकेस भी किया जिनमें से कुछ और भविष्य में भारत लाया जा सकता है। इनमें से एक इलेक्ट्रिक एसयूवी Vinfast VF3 भी है, जिसे एक्सपो में पेश किया गया था। दो दरवाजों वाली इस गाड़ी में चार लोगों के साथ सफर किया जा सकता है और इसकी रेंज 215 किलोमीटर तका हो सकती है। इसकी संभावित एक्स शोरूम कीमत 10 लाख रुपये तक हो सकती है।

इलेक्ट्रिक गाड़ी लाने से पहले तैयार कर रहे पूरा इको सिस्टम, पांच से 10 किलोमीटर में लगाएंगे फास्ट चार्जर-मारुति

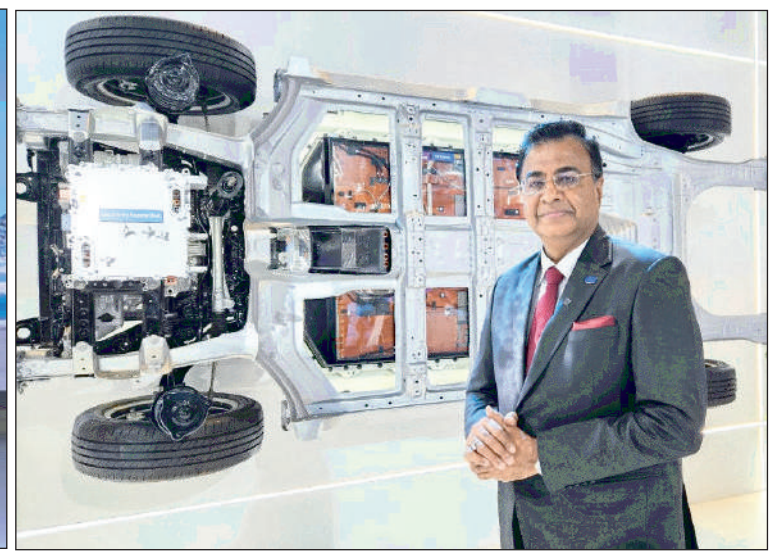

परिवहन विशेष न्यूज

देश की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से Auto Expo 2025 में पहली EV के तौर पर Maruti E Vitara को पेश किया गया है। कंपनी इसे कब तक लॉन्च कर सकती है। कंपनी की प्राथमिकताएं क्या हैं। ईवी से क्या उम्मीद है। ईवी के लिए किस तरह ईको सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता Maruti Suzuki की ओर से 17 से 22 जनवरी 2025 के बीच हुए Auto Expo 2025 के दौरान पहली Electric SUV के तौर पर Maruti E VITARA को पेश किया गया है। एसयूवी को पेश करने के बाद Maruti के सीनियर एग्जीक्यूटिव अधिकारी पार्थो बैनर्जी से Jagran.com ने खास बात की। इस दौरान Maruti E VITARA और Electric Vehicles को बढ़ावा देने के लिए जरूरी Ecosystem तैयार करने के लिए कंपनी की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

सवाल – मारुति की Maruti E VITARA कैसी गाड़ी है और इसे किस तरह से डेवलप किया गया है।

जवाब – मारुति की नई Maruti E VITARA एक Pure E Born प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। इसका व्हीलबेस 2700 एमएम है। जिस कारण इसमें ज्यादा जगह मिल पाती है। जिससे ऐसी गाड़ी में सफर करना ज्यादा आरामदायक हो जाता है। इसकी रियर सीट भी स्लाइडिंग है और 160 एमएम की स्लाइडिंग इसमें होती है। इसके साथ ही मारुति ने Maruti E VITARA को एसयूवी सेगमेंट में पेश किया है। जिसमें रेंज काफी महत्वपूर्ण होती है। कई ग्राहकों को इस बात की चिंता होती है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से ज्यादा लंबी दूरी तय करने में परेशानी होती है लेकिन Maruti E VITARA सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी को तय करेगी। Maruti Maruti E VITARA का इंटीरियर प्राइवेट जेट के इंटीरियर की तरह बनाया गया है। सुरक्षा के लिए इसमें सात एयरबैग दिए गए हैं जिसके साथ ADAS सहित कई सेफ्टी फीचर्स को दिया जा रहा है।

सवाल – कंपनी की ओर से ई- विटारा को पेश किया जा चुका है। लेकिन EV के लिए किस तरह से ईको सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

जवाब – मारुति की ओर से E For Me को शुरू किया गया है। जिसमें दो E दिए गए हैं। छोटे E का मतलब E Vitara और जो ईकोसिस्टम हम ऑफर करने जा रहे हैं। वहीं बड़े E का मतलब अर्थ है। मारुति विटारा के साथ जो भी व्यक्ति इस सिस्टम से जुड़ेगा उससे वह अर्थ को बचाने में अपना योगदान दे पाएगा। इसके लिए हम टॉप -100 शहरों में फास्ट चार्जर लगा रहे हैं। हर पांच से 10 किलोमीटर में गाड़ी चार्ज करने के लिए चार्जर की सुविधा को उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही भारत में मारुति की एक हजार से ज्यादा वर्कशॉप को ईवी इनेबल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की ओर से सर्विस ऑन व्हील्स को भी ऑफर किया जा रहा है जिससे ईवी इनेबल्ड वर्कशॉप के पास न होने पर भी सर्विस ऑन व्हील्स के जरिए ग्राहकों की परेशानी को दूर किया जा सकेगा।

सवाल – ई विटारा से इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आ रहे हैं। कंपनी की ओर से कब तक इसे औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है।

जवाब – मारुति की सोच यह है कि पहले ग्राहकों को बेहतरीन ईको सिस्टम मिलना चाहिए। इसके बाद ही गाड़ी को बाजार में आना चाहिए। अगर पहले गाड़ी को दे दिया जाए और ईको सिस्टम सही न हो तो फिर बाद में परेशानी होती है। हम इस गाड़ी को तभी बिक्री के लिए उपलब्ध करवाएंगे जब ईको सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।

सवाल – मारुति की ओर से ईको सिस्टम को कब तक पूरी तरह से तैयार किया जा सकता है।

जवाब– ईको सिस्टम पर काम जारी है। टीम इस पर काम कर रही है। काफी जल्द इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

सवाल – मारुति की E VITARA कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। ऐसे में कंपनी को इससे क्या उम्मीद हैं।

जवाब – मारुति कभी भी छोटा सोचकर नहीं आती, हमेशा बड़ा सोचकर ही कंपनी बाजार में किसी उत्पाद को ऑफर करती है। कंपनी ने E VITARA को Auto Expo 2025 में पेश किया है। जिसके बाद लोगों को यह काफी पसंद आ रही है। हम भारत की जनता को निराश नहीं करेंगे।

सवाल – मारुति की ओर से पेश की गई E VITARA का मुकाबला Auto Expo 2025 में ही लॉन्च हुई Hyundai Creta Electric के साथ होगा। ऐसे में क्या Maruti E Vitara की संभावित कीमत क्या हो सकती है।

जवाब – मारुति की ओर से पेश की गई E VITARA की कीमतों की जानकारी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन, अगर आपको बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचनी है तो सिर्फ गाड़ी से काम नहीं होगा। इसके लिए पूरा ईको सिस्टम तैयार होना चाहिए। हमारी कोशिश सिर्फ गाड़ी बेचना नहीं है, बल्कि पूरे ईको सिस्टम को तैयार करना है।

सवाल – Maruti E VITARA के बाद क्या इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाएगा और किस तरह की कारों को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में लाया जा सकता है।

जवाब – हमारी ओर से कमिटमेंट किया गया है कि हम अगले पांच साल में पांच नई ईवी कारों को लाएंगे।

क्यों दक्षिण विज्ञान की ओर अधिक झुकता है?

विजय गर्ग

प्राचीन योगदानः स्कूल और कॉलेजों में विज्ञान और अन्य एसटीईएम शाखाओं (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) का प्रारंभिक स्तर से दक्षिण भारतीय शिक्षा प्रणालियों में महत्व है। यह लेख बताता है कि दक्षिण भारत विज्ञान के प्रति अधिक क्यों झुकता है। भारत में 42 लाख छात्रों ने 2022 में विज्ञान चुना, ज्यादातर दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश 75.63% विज्ञान स्ट्रीम छात्रों के साथ नेतृत्व करता है दक्षिण भारत के पास देश की एमबीबीएस सीटें का 41% हिस्सा है प्रत्येक हाई स्कूल के छात्र को एक मोड़ का सामना करना पड़ता हैः विज्ञान, वाणिज्य या मानविकी। अधिकांश के लिए, यह मोड़ है जो उनके भविष्य को तय करता है। 2022 में, भारत में 42 लाख छात्रों ने विज्ञान धारा को चुना। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से अधिकांश पांच दक्षिणी राज्यों - तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक से आए थे। यह कोई संयोग नहीं है; यह संस्कृति, बुनियादी ढांचे और युवा दिमागों के पोषण के अवसरों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का परिणाम है। एक क्षेत्रीय वरीयता 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एक अध्ययन के अनुसार, पूरे भारत में स्ट्रीम चयन में कुछ आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि हैं। आंध्र प्रदेश ने विज्ञान का चयन करने वाले कक्षा 11 के छात्रों के 75.63% के साथ पैक का नेतृत्व किया, इसके बाद तेलंगाना को 64.59% और तमिलनाडु 61.50% पर। आंकड़े राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर हैं, जो दक्षिण भारत के विज्ञान की ओर मजबूत झुकाव की ओर इशारा करता है। आधारभूत संरचना दक्षिण भारत में विज्ञान के साथ एक प्रेम संबंध है, जो संसाधनों और अवसरों की एक उत्कृष्ट नींव द्वारा समर्थित है। इस क्षेत्र में कई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, अनुसंधान केंद्र और नवाचार हब हैं। कुछ नाम हैः बेंगलुरु में इसरो अंतरिक्ष विज्ञान को प्रोत्साहित कर रहा है NAL और CLRI में हैंड्स-ऑन रिसर्च सुविधाएं उपलब्ध हैं शिक्षा -शक्ति पांच दक्षिणी राज्य और पुदुचेरी और लक्षद्वीप हाउस 1,229 एआईसीटीई-अनुमोदित संस्थान जो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। यह क्षेत्र प्रति वर्ष लगभग 5.11 लाख छात्रों की सेवन क्षमता समेटे हुए है और तकनीकी शिक्षा में अग्रणी है। प्रतिस्पर्धा में बढ़त आईआईटी मद्रास ज़ोन हमेशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) में शीर्ष पर रहता है। 2022 में, इस क्षेत्र के 29 छात्र शीर्ष 100 में थे। ₹बेंगलुरु ने अकेले 2022 (नेसकाम) में भारत के तकनीकी स्टार्टअप के 30% से अधिक का हिसाब दिया। स्टेम की सफलता तमिलनाडु और कर्नाटक में स्पष्ट है, 2023 में शीर्ष 500 जेईई उन्नत रैंक धारकों में से 21.3% का योगदान है। जेईई और एनईईटी कोचिंग सेंटर, ₹डॉ। जगदीश भरतम ने कहा कि गितम स्कूल ऑफ साइंस, विशाखापत्तनम में भौतिकी विभाग में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। चिकित्सा शिक्षा में, दक्षिण भारत में देश की एमबीबीएस सीटों का 41 प्रतिशत है। इस क्षेत्र के 242 मेडिकल कॉलेजों में से लगभग 60 प्रतिशत निजी तौर पर चलते हैं, जो एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है जो डॉक्टरों का पोषण करता है। अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाना कक्षाओं के अलावा, दक्षिण भारत में कई योगदान हैं। एक और लॉन्च पैड आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विकास के अधीन है। इसे 3,985 करोड़ रुपये में मंजूरी दी गई है। इस तरह का कार्यक्रम आकांक्षाओं को बढ़ाता है और क्षेत्र की वैज्ञानिक ताकत को बढ़ाता है। बौद्धिक उत्कृष्टता की एक विरासत दक्षिण भारत में विज्ञान के लिए जुनून का एक लंबा इतिहास हैः प्राचीन योगदानः आर्यभत से केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स तक, यह क्षेत्र बौद्धिक गतिविधि के लिए एक केंद्र है जो कई शताब्दियों से पहले है। औपनिवेशिक प्रभावः ब्रिटिश शासन ने शहरों को बदल दिया हैजैसे चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद को शैक्षिक केंद्रों में बदलना। आईआईएससी बेंगलुरु और मद्रास मेडिकल कॉलेज का जन्म इसी अवधि में हुआ। आधुनिक प्रतीकः इसरो जैसे संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, और डॉ. ए.पी.जे. जैसी हस्तियाँ। अब्दुल कलाम, वे ही लोग हैं जिन्होंने वास्तव में दक्षिण भारत में वैज्ञानिक उत्कृष्टता की प्रतिष्ठा को मजबूत किया है। सीखने की संस्कृति परिवार सीखने को प्राथमिकता देते हैं, और स्कूल कम उम्र से ही एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) पर जोर देते हैं। यह समर्पण एक पुण्य चक्र बनाता हैः मजबूत स्कूल असाधारण छात्र पैदा करते हैं जो अगली पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-21 के अनुसार, तमिलनाडु उच्च शिक्षा में 52.5% के सकल नामांकन अनुपात के साथ देश में अग्रणी है, जिसका अधिकांश भाग एसटीईएम क्षेत्रों पर केंद्रित है। परिवार इंजीनियरिंग और चिकित्सा में करियर को प्राथमिकता देते हैं, तमिलनाडु के 58% माता-पिता अपने बच्चों के लिए इन रास्तों को प्राथमिकता देते हैं (एएसईआर 2022)। डॉ. जगदीश भरतम ने कहा, ₹दक्षिण भारत में उच्च अंग्रेजी दक्षता एक विशिष्ट लाभ प्रदान करती है। केरल, 96.2% की साक्षरता दर के साथ, अंग्रेजी-माध्यम शिक्षा में अग्रणी है, जिससे छात्रों को विज्ञान पाठ्यक्रमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और वैश्विक अवसरों तक पहुंचने में मदद मिलती है।₹ अकेले हैदराबाद में, 1,000 से अधिक कोचिंग सेंटर जेईई और एनईईटी के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 400 से भी कम कोचिंग सेंटर आईआईटी और एम्स जैसे शीर्ष संस्थानों के लिए अधिक संरचित मार्ग प्रदान करते हैं। नीति और निवेश दक्षिणी शहरों में आर्थिक विकास एक प्रमुख चालक रहा है। 2021 में $110 बिलियन की जीडीपी के साथ बेंगलुरु, आईटी और बायोटेक में प्रतिभा के लिए एक चुंबक है। 2023-24 के लिए कर्नाटक के 31,980 करोड़ रुपये के शिक्षा बजट में एसटीईएम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश शामिल है। चेन्नई का औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान का समर्थन करता है, उसी वर्ष तमिलनाडु ने शिक्षा के लिए 40,299 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। दक्षिणी राज्य शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। ये उच्च एवं तकनीकी अध्ययन को अधिक महत्व देते हैं। वीआईटी, अन्ना विश्वविद्यालय और भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान विश्व स्तरीय शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में क्षेत्र के उत्साह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर और दक्षिण में विज्ञान के लिए बजट का आवंटन सरकार अटल इनोवेशन मिशन, स्किल इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 जैसी पहलों के माध्यम से समान आवंटन नीतियों को बनाए रखती है। जबकि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना है, दक्षिणी राज्यों को ऐतिहासिक रूप से इसरो (बेंगलुरु) और जैसे संस्थानों में निवेश से लाभ हुआ है। डीआरडीओ (हैदराबाद) ने उन्हें बढ़त दिला दी। उदाहरण के लिए, 2023 के लिए इसरो का कुल वार्षिक बजट 13,949 करोड़ रुपये था, जिसमें से अधिकांश दक्षिण में मुख्यालय वाली परियोजनाओं पर खर्च किया गया है। प्रोफेसर ने आगे बताया, ₹भारत का समग्र अनुसंधान एवं विकास व्यय, सकल घरेलू उत्पाद (2022) का केवल 0.7% है, जो दोनों क्षेत्रों की अत्याधुनिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने की क्षमता को सीमित करता है। हालांकि, एनईपी 2020 का लक्ष्य सभी राज्यों में अंतःविषय शिक्षा और नवाचार को प्राथमिकता देकर इक्विटी को बढ़ाना है।₹ . राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, क्षेत्रीय विज्ञान पार्क और ऊष्मायन केंद्रों की स्थापना पहले से ही देखी जा रही है, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को एसटीईएम-केंद्रित स्कूलों की स्थापना के लिए अनुदान मिल रहा है। दक्षिण भारत उन्नत इंजीनियरिंग से लेकर अत्याधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने वाले प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है, इस क्षेत्र ने हमेशा ज्ञान का जश्न मनाया है। विज्ञान के प्रति दक्षिण भारत की प्राथमिकता में यह एक आंकड़े से कहीं अधिक है। यह शिक्षा और प्रगति के प्रति उसके समर्पण को प्रमाणित करता है। निवेश के साथ Iएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट पोषण, और अपनी समृद्ध विरासत का सम्मान करते हुए, यह क्षेत्र बड़े सपने देखने के लिए पूरे देश में छात्रों को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ता है। यह रुझानों और संख्याओं के बारे में नहीं है, हालांकि। यह एक ऐसे क्षेत्र के बारे में है जिसने शिक्षा को जीवन का एक तरीका बनाया है। यदि उचित नींव बनाया गया है, तो आकाश सीमा नहीं होगी-यह केवल शुरुआती बिंदु है। इस तरह के सुधारों के साथ, भारत क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए अच्छी तरह से तैनात है।

पाठ्यक्रमों में बदलाव सत्ता पाने का हथियार

विजय गर्ग

सरकारों का जोर ज्यादातर राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और हिंदी की पुस्तकों पर सुविधा के हिसाब से बदलाव पर जो रहा है। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। जो भी दल भविष्य में सत्ता में आएगा, पाठ्यक्रमों में फिर वही बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। इससे और कुछ हो न हो, पर विद्यार्थी दिग्भ्रमित जरूर होते हैं। पुराविदों, शिक्षाविदों के साथ न्यायविदों से इस पर विमर्श होना चाहिए

देश के नेताओं ने सत्ता पाने के लिए शिक्षा को भी राजनीतिक हथियार बनाया है। सत्ता बदलते ही नेता अपनी विचाराधारा के हिसाब से स्कूल-कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में बदलाव करके वोट बैंक को पक्का करने की जुगत में लगे रहते हैं। विद्यार्थी इन सबके बीच फुटबाल बने रहते हैं। उन्हें वही पढना होता है जोकि सरकारें उन्हें पाठ्यक्रमों के जरिए पढ़ाती हैं। बेशक तथ्य तोड़-मरोड़ कर ही क्यों न पेश किए जाएं। हालात यह हैं कि सत्ता में बदलाव के साथ पाठ्यक्रम भी बदलते रहते हैं। देश में शिक्षा में इस तरह के बदलाव पर लंबे अर्से से बहस छिड़ी हुई है। राजनीतिक दल बदलाव को लेकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसी कड़ी में नया विवाद कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी की किताब के सिलेबस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि इसमें गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कर्नाटक विश्वविद्यालय के अंडरग्रेजुएट विद्यार्थियों के पहले सेमेस्टर की किताब में ऐसा कंटेंट लिखा गया है, जिससे भारत की एकता बाधित होती है। कथित तौर पर सिलेबस में संघ परिवार, राम मंदिर के निर्माण और भारत माता आदि की आलोचना की गई थी और कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। सिलेबस में आरएसएस की आलोचना करने के लिए बार-बार 'संघ परिवार' जैसे शब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, तब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता में आने पर आरोप लगाए थे कि पूर्ववर्ती सिद्धारमैया सरकार ने महज अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टिकरण और कम्युनिस्ट विचारधारा थोपने के लिए किताबों में विभिन्न बदलाव किए थे।

इस दावे की पुष्टि करते हुए सरकार ने कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को दिखाने के लिए 200 पृष्ठों की किताब भी जारी की थी, जिसमें पाठ्य पुस्तकों में हिंदू देवताओं और ऐतिहासिक आंकड़ों को गलत तरीके से पेश किया गया। भाजपा का आरोप था कि विजयनगर के शासकों, मैसूर राजाओं वडियारों, राष्ट्र कवियों कुवेम्पु, बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा और सर एम. विश्वेश्वरैया पर अध्यायों को या तो हटा दिया गया या उन पर सामग्री कम कर दी गई। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने टीपू सुल्तान, मोहम्मद गजनवी, हैदर अली और मुगलों का बखान किया। सत्ता में आने पर भाजपा ने टीपू, हैदर अली, गजनवी और मुगलों पर अध्यायों को अब हटा दिया और स्वतंत्रता सेनानियों तथा मराठा शासक शिवाजी और केम्पेगौड़ा जैसी ऐतिहासिक शख्सियतों को पाठ्य पुस्तकों में प्रमुखता दी गई। राजनीतिक नजरिए से पाठ्यक्रमों में राज्य ही नहीं, केंद्र में जो भी सरकार सत्ता में रही, उसने अपनी दलीलों के साथ बदलाव

किए हैं। यह सब किया जाता है देशहित और संस्कृति-सभ्यता के इतिहास को बचाने के नाम पर। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान पाठ्य पुस्तक में गुजरात दंगों के बारे में अध्याय जोड़ दिया गया। इस अनुच्छेद में दो परिवर्तन किए गए। अनुच्छेद में शामिल शीर्षक मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगे को बदलकर गुजरात दंगे कर दिया गया। इसी अनुच्छेद के पहले वाक्य से मुस्लिम शब्द भी हटा दिया गया। अनुच्छेद के शीर्षक के अलावा अनुच्छेद के अंदर के पाठ को नहीं छुआ गया। गुजरात में भाजपा शासन के दौरान 2002 में हुए मुस्लिम विरोधी गुजरात दंगों का संदर्भ पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया गया है, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान हुए सिख विरोधी दंगों को बरकरार रखा गया। वर्ष 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से यह तीसरी बार है, जब सरकार ने पाठ्य पुस्तक संशोधन की कवायद की। इससे पहले 2017 और 2019 में पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया गया था।

हटाए गए खंडों में मुगलों पर एक पूरा अध्याय शामिल है, जो एक मुस्लिम राजवंश था, जिसने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया और भारत के संस्थापक पिता मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा हिंदू-मुस्लिम एकता की खोज की चर्चा से संबंधित पाठ को हटाया गया। गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की ब्राह्मण उत्पत्ति और भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर लगाए गए संक्षिप्त प्रतिबंधों को सुविधाजनक रूप से हटा दिया गया, जैसा कि 2002 के गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों को भी हटाया गया। वर्ष 2022 में एनसीईआरटी ने स्कूलों की किताबों में बदलाव किए। इनमें प्राचीन और मध्ययुगीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के बारे में अभी तक पढ़ाए जाने वाले कई तथ्यों को हटा दिया गया। मम्लूक, तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगल साम्राज्य समेत सभी मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में जानकारी देने वाले कई पन्नों को हटाया गया। जाति व्यवस्था से भी जुड़ी काफी जानकारी को हटा दिया गया, जैसे वर्ण प्रथा वंशानुगत होती है, एक श्रेणी के लोगों को अछूत बताना, वर्ण प्रथा के खिलाफ विरोध, 2002 के गुजरात दंगे, आपातकाल, नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे जन आंदोलनों आदि जैसी आधुनिक भारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी को भी हटा दिया गया। पाठ्य पुस्तकों से विवादास्पद हटाए गए तथ्यों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि भाजपा-आरएसएस पाठ्य पुस्तक की सामग्री बदल सकते हैं, लेकिन वे इतिहास को नहीं मिटा सकते। भाजपा सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों के भगवाकरण की व्याख्या करते हुए, केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा था कि संघ परिवार इतिहास के निरंतर भय में रहता है, क्योंकि यह उनके असली चेहरे को उजागर करता है। वे इतिहास को फिर से लिखने और उसे झूठ से ढकने का सहारा लेते हैं। संघ परिवार में आरएसएस और भाजपा सहित उसके संबद्ध संगठन शामिल हैं। रोमिला थापर और जयंति घोष जैसे प्रख्यात शिक्षाविदों, जिन्होंने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पिछले संस्करण लिखे हैं, ने एक सार्वजनिक बयान जारी कर हटाए गए शब्दों को वापस लेने की मांग की थी।

इन बदलावों को विभाजनकारी उद्देश्यों से प्रेरित बताते हुए बयान में कहा गया कि किताबें लिखने वालों से सलाह लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यह एक ऐसा निर्णय है जो भारतीय उपमहाद्वीप के संवैधानिक लोकाचार और समग्र संस्कृति के खिलाफ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम में अहम बदलाव किए। ये बदलाव सिंधु घाटी सभ्यता के उदय और पतन को लेकर हैं। ये बदलाव हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से प्राप्त प्राचीन डीएनए के अध्ययन के आधार पर किए गए। इस अध्ययन से माना जाता रहा कि आर्यों के आगमन का सिद्धांत गलत साबित होता है। सरकारों का जोर ज्यादातर राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और हिंदी की पुस्तकों पर सुविधा के हिसाब से बदलाव पर जो रहा है। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है। जो भी दल भविष्य में सत्ता में आएगा, पाठ्यक्रमों में फिर वही बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। इससे और कुछ हो न हो, पर विद्यार्थी दिग्भ्रमित जरूर होते हैं। इसलिए बेहतर है कि पाठ्यक्रमों में बदलाव के लिए देश के पुराविदों, शिक्षाविदों के साथ न्यायविदों को भी शामिल किया जाए ताकि चुनावी गणित के हिसाब से ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ का सिलसिला बंद हो सके।

चीन 'आर्टिफिशियल सन' बनाता है, पृथ्वी पर 18 मिनट के लिए 100 मिलियन डिग्री की गर्मी को बनाए रखते हुए एक रिकॉर्ड सेट करता है

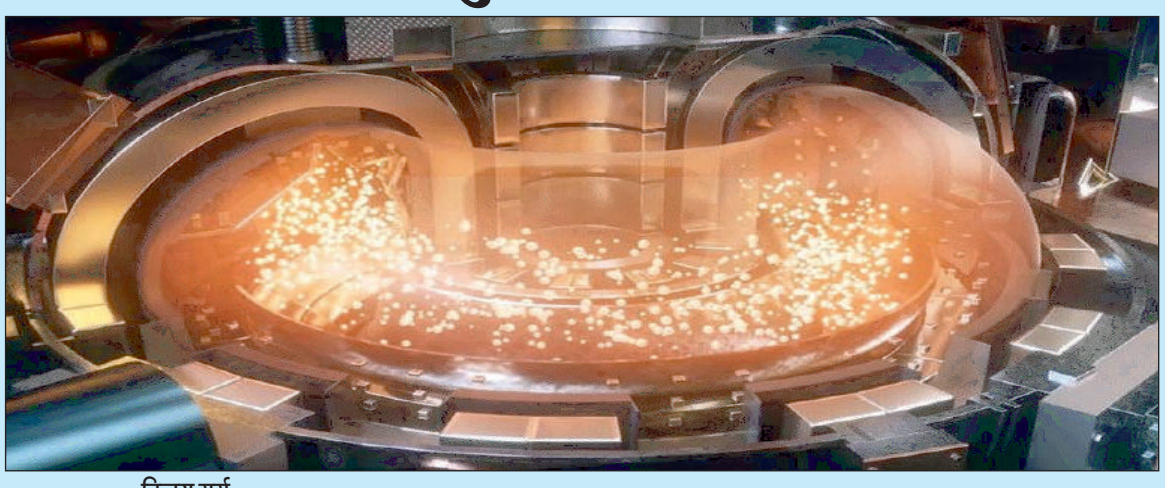

विजय गर्ग

चीनी वैज्ञानिकों ने लगभग 18 मिनट के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लाज्मा तापमान को बनाए रखते हुए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे असीम स्वच्छ ऊर्जा की खोज को आगे बढ़ाया गया।

चीनी वैज्ञानिकों ने लगभग 18 मिनट के लिए 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक प्लाज्मा तापमान को बनाए रखते हुए एक उल्लेखनीय विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। यह सफलता प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (पूर्व) का उपयोग करके हासिल की गई थी, एक परमाणु संलयन रिएक्टर को अक्सर ₹कृत्रिम सूर्य₹ कहा जाता है।

असीमित ऊर्जा की ओर एक कदम प्रयोगात्मक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (पूर्व) सुविधा में प्रयोग किया गया था। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम गैसों का उपयोग करते हुए, वैज्ञानिकों ने सूर्य को शक्ति देने वाली संलयन प्रक्रिया की नकल की। यह ₹कृत्रिम सूर्य₹ प्रयोग परमाणु संलयन को एक व्यवहार्य ऊर्जा स्रोत बनाने की दिशा में एक कदम है।

पूर्व के निर्देशक, सॉन्ग यंटाओ ने समझाया कि आत्मनिर्भर प्लाज्मा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। ₹फ्यूजन उपकरणों को बिजली का उत्पादन करने के लिए हजारों सेकंड के लिए संचालित करना चाहिए,₹ उन्होंने कहा। हालांकि, ऐसी तीव्र परिस्थितियों को बनाए रखने में सक्षम रिएक्टरों का निर्माण एक महत्वपूर्ण चुनौती है, एफपी ने बताया।

प्रोफेसर झोउ हैशन ने एक बड़ी बाधा के रूप में सामग्री लचीलापन पर प्रकाश डाला। ₹क्षति-प्रतिरोधी सामग्री विकसित करना बेहद जटिल है,₹ झोउ ने कहा, परीक्षण के लिए उन्नत सिमुलेशन वातावरण आवश्यक हैं।

भविष्य की योजना और फ्यूजन का वादा चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम 2035 तक एक औद्योगिक प्रोटोटाइप फ्यूजन रिएक्टर बनाने पर केंद्रित है। लक्ष्य 2050 तक बड़े पैमाने पर संलयन प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना है।

परमाणु संलयन सूर्य की नकल करता है, अपार तापमान पर हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्यूज करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। यदि सफल, तो फ्यूजन एक स्वच्छ, सुरक्षित और लगभग असीम ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकता है।

फ्यूजन परमाणु संलयन के पीछे के विज्ञान में हल्के परमाणु नाभिक, हाइड्रोजन आइसोटोप की तरह, भारी ऊर्जा जारी करने के लिए, अपार ऊर्जा जारी करना शामिल है। इस प्रक्रिया में सूर्य के मूल के समान अत्यधिक गर्मी और दबाव की आवश्यकता होती है, और प्रतिक्रिया को शामिल करने के लिए चुंबकीय क्षेत्रों जैसे उन्नत तरीकों का उपयोग करता है।

फ्यूजन प्रचुर मात्रा में ईंधन और न्यूनतम अपशिष्ट के साथ स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि, पृथ्वी पर इन स्थितियों की प्रतिकृति और नियंत्रित करना एक चुनौती है। बाधाओं के बावजूद, वैज्ञानिकों ने परमाणु संलयन की क्षमता का दोहन करने के लिए अपनी खोज जारी रखी।

चांदनी चौक : खास जुड़ाव रहा

विजय गर्ग

दिल्ली ही नहीं, देश का पहला सबसे आलीशान बाज़ार चांदनी चौक 2021 की गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में भी दिखाई दिया था। चांदनी चौक वाक़ई ख़ास है क्योंकि लाल किले के साथ ही बना, और यहीं देश का पहला घंटा घर खड़ा हुआ और उसी पर 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया गया। साल 1950 से 2000 तक गणतंत्र दिवस परेड भी चांदनी चौक की सड़कों से ही गुज़रकर लाल क़िले पर ठहरती थी।

वर्ष 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली वालों के दिलों में बसा चांदनी चौक की झांकी आकर्षण का केंद्र रही थी। क्योंकि चांदनी चौक मुगल बादशाहत से अंग्रेज़ी हुकूमत से होते- होते आज़ाद भारत की भी शान है। साल 1950 से 2000 तक गणतंत्र दिवस की परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू हो कर, राजपथ (अब कर्तव्य पथ) पर राष्ट्रपति की सलामी के बाद कनॉट प्लेस से अजमेरी गेट से नया बाजार, लाहौरी गेट से खारी बावली और फिर फतेहपुरी मस्जिद होते-होते चांदनी चौक में पहुंचती थी। इनमें टैंक, रॉकेट और युद्ध के अत्याधुनिक साज-सामानों के साथ राज्यों-मंत्रालयों की झांकियां होती थीं। अपना हुनर दिखाते सेना के जवान भी गुजरते थे। देशभक्ति के नारे गूंजते थे। परेड लाल क़िले पर जाकर संपन्न होती थी। यह सिलसिला साल 2000 तक जारी रहा। अगले सालों में सुरक्षा कारणों से परेड का रास्ता बदला गया। अब परेड बहादुरशाह जफर मार्ग और दरियागंज के नेताजी सुभाष मार्ग होते हुए सीधे लाल क़िले पहुंचने लगी। हालांकि अब भी कई दिनों तक झांकियां वहीं खड़ी रहती हैं, ताकि देशवासी आ कर देख सकें।

सौंदर्यीकरण के बाद का नजारा

सन1639 से 1648 के आसपास बनने के क़रीब पौने चार सौ साल बाद चांदनी चौक की नई बदली ख़ूबसूरती हाल के सालों में फिर देखने को मिली है। सौंदर्यीकरण के बाद लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक क़रीब 1.3 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक सड़क पर चलते-चलते राहगीर थक जाएं, तो बैठने-सुस्ताने के लिए लाल पत्थर के नक्क़ाशीदार चबूतरे बने हैं। यूं भी, चांदनी चौक पर गौरी शंकर मंदिर, सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, शीशगंज गुरुद्वारा और फतेहपुरी मस्जिद हर धर्म के धार्मिक स्थल हैं। साइकिल मार्केट, भागीरथ पैलेस, दरीबा कलां, फ़व्वारा चौक, नई सड़क, बल्लीमारन, फतेहपुरी वगैरह इसके साथ विविध बाज़ार जुड़ते हैं। चांदनी चौक बदलता रहा है। हालिया सौंदर्यीकरण से पहले 1990 के दशक में, तत्कालीन सांसद के प्रयासों से चांदनी चौक की खोई शान लौटाने की कोशिश भी की गई। उन्होंने अपने सांसद कार्यकाल में चांदनी चौक के बीचोंबीच दो दफ़ा 'चौदहवीं का चांद' नाम से उत्सव आयोजित किए। सड़क और दोनों ओर की इमारतों को रंग-रोगन कर चमकाया। मेन बाज़ार में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए।

पुरानी दिल्ली का दिल

चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का दिल है। लाल क़िले के पश्चिम या कहें लाहौर दरवाज़े के सामने है चांदनी चौक। मुगलिया दौर के बाद हाल के सालों में एक बार फिर इसकी शानो-शौकत लौटी है। भीड़भाड़ नहीं घटी, पैदल चलना बेशक आसान हुआ है। शाही शान तो बरकरार रहेगी ही। हेरिटेज जानकार और 'दिल्ली 14 हिस्टॉरिकल वॉक्स' की लेखिका स्वप्ना लिडल कहती हैं- लाल क़िले से फ़व्वारे तक सड़क को देख हेरिटेज प्रेमी गदगद हैं। इससे शीशगंज गुरुद्वारे से लालकिले के स्पष्ट दीदार होने लगे हैं।

अशर्फी बाजार ऐसे बना चांदनी चौक

शाहजहांनाबाद यानी मुगल बादशाह शाहजहां के शहर का सबसे अहम हिस्सा था चांदनी चौक। सन् 1648 में लालकिला बनाने के बाद ही शाहजहां ने शहर बसाने पर गौर किया। उस ज़माने में, शायद बाजार को चौक नाम से ज्यादा पुकारा जाता था। कहा जाता है, 17वीं सदी में, मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी शहजादी जहांआरा ने मनीचेंज मार्केट बनवाई थी, अशर्फी बाजार। जिसके बीचोंबीच तालाब या नहर बहती थी। पूर्णिमा की रात चांद की परछाई तालाब में पड़ती और बाजार चांदनी की रोशनी से दमक उठता। बस इसी से बाजार का नामकरण हो गया चांदनी चौक।

कई बदलावों से गुजरा ये इलाका

बीते 375 सालों में शाहजहांनाबाद कई बदलावों का गवाह रहा है। सबसे पहला बदलाव 1857 में आया, जब आज़ादी की पहली जंग को दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों पर दमनकारी आक्रमण किए। नवाबों की शानदार हवेलियों पर धुंधले बादल छाने लगे। उनमें ज्यादा आबादी बसने लगी। दिल्ली के पहले लखपति लाला छुन्नामल की हवेली भी चांदनी चौक के बीचोंबीच है। इसमें दिल्ली की पहली कार आई, पहली बिजली लाइन पड़ी और पहली बार टेलीफोन की घंटी बजी। रेल के आगमन के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाने के लिए उत्तरी शाहजहांनाबाद की कई गलियों और हवेलियों को कुर्बान होना पड़ा। और आज शाहजहांनाबाद घनी आबादी वाला इलाका बनकर उभरा है। यहां सालों-साल ट्राम भी दौड़ती रही। अब दो मेट्रो लाइनों और चांदनी चौक व लालक़िला नाम के दो मेट्रो स्टेशनों से जुड़ा है। चांदनी चौक के मोती, कुमार, मैजिस्टिक और जुलबी चारों सिनेमाघर अर्से से बंद हो चुके हैं, लेकिन यहीं बीते साल ओमेक्स चौक मॉल चालू हुआ है।

सबसे पहला घंटाघर

बताया जाता है कि देश का सबसे पहला घंटाघर चांदनी चौक के बीचोंबीच बना था, सन् 1870 में। लेकिन कुछ हिस्से खुद-ब-खुद गिरने के बाद 1950 के दशक में पूरी तरह हटा दिया गया। इसकी लोकेशन दिल्ली का ऐन सेंटर माना जाता है। अन्य शहरों में इसके बाद ही घंटाघर बने। सबसे फेमस 128 फुट ऊंचा चांदनी चौक का घंटाघर तब 28,000 रुपये में दिल्ली म्युनिसिपेलिटी ने बनवाया था। इसे नॉर्थब्रूक क्लॉक टॉवर के नाम से जानते थे। 15 अगस्त 1947 से घंटाघर के ऊपर तिरंगा फहराया गया। और तो और, मृत्यु के तीन साल बाद महात्मा गांधी की देश और राजधानी में संभवतः पहली आदमकद प्रतिमा राजधानी के चांदनी चौक के टाउन हॉल के पीछे कंपनी बाग में 1952 में लगी थी। टाउन हाल की इमारत खुद तो डेढ़-पौने दो सदी से ज्यादा पुरानी है, और बीते डेढ़ दशक से खाली पड़ी है, लेकिन अभी तक न दिल्ली म्यूजियम बन सका है, न हेरिटेज होटल। साल-दो साल में चर्चाएं ज़ोर पकड़ती हैं, फिर टांय-टांय फिस। कामना कीजिए कि चांदनी चौक की शाही शान यूं ही सलामत रहे।

2025-26 में 10.4% बढ़ेगा सकल कर संग्रह, सरकार को मिलेंगे 41 लाख करोड़

परिवहन विशेष न्यूज

रिपोर्ट के मुताबिक, सकल कर संग्रह के अनुमान में वृद्धि राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत आर्थिक सुधार और प्रभावी राजस्व उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि, संभावित राहत उपायों के कारण आयकर संग्रह कम होने की वजह से 2025-26 में प्रत्यक्ष कर राजस्व 9 .6 फीसदी की धीमी रफ्तार से बढ़कर 23 .3 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है।

आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण 2025-26 में भी कर संग्रह के रूप में सरकार की कमाई मजबूत बनी रहने की उम्मीद है। केयरएज रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा, अगले वित्त वर्ष में कर वसूली अच्छी रहेगी। सकल कर राजस्व 10.4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 41.4 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है। बढ़ोतरी की यह रफ्तार 2025-26 के लिए अनुमानित 10.3 फीसदी की नॉमिनल जीडीपी वृद्धि से थोड़ा अधिक है। शुद्ध कर राजस्व के रूप में सरकार की झोली में 28.2 लाख करोड़ रुपये आ सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, सकल कर संग्रह के अनुमान में वृद्धि राजकोषीय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सतत आर्थिक सुधार और प्रभावी राजस्व उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। हालांकि, संभावित राहत उपायों के कारण आयकर संग्रह कम होने की वजह से 2025-26 में प्रत्यक्ष कर राजस्व 9.6 फीसदी की धीमी रफ्तार से बढ़कर 23.3 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है। आर्थिक वृद्धि में सुधार के कारण कॉरपोरेट कर संग्रह में भी एक साल पहले की तुलना में 11.4 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

जीएसटी वसूली 11.8 लाख करोड़

अप्रत्यक्ष कर वसूली के रूप में सरकार को 18.1 लाख करोड़ रुपये की कमाई हो सकती है, जो सालाना आधार पर 11.9 फीसदी की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें जीएसटी का योगदान 11.4 फीसदी बढ़कर 11.8 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है।

खाद्य तेल पर उच्च टैरिफ के कारण सीमा शुल्क संग्रह में भी 20 फीसदी की मजबूत वृद्धि की संभावना है। घरेलू उद्योगों के लिए सुरक्षात्मक उपायों से राजस्व में और वृद्धि हो सकती है।

आरबीआई से सरकार को कम मिलेगा लाभांश

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले वित्त वर्ष में गैर-कर राजस्व 9.8 फीसदी घटकर 4.8 लाख करोड़ रुपये रह सकता है। आरबीआई से सरकार को मिलने वाला लाभांश 1.1 लाख करोड़ से 1.3 लाख करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान है, जो बीते वित्त वर्ष के 2.1 लाख करोड़ रुपये से काफी कम है।

विनिवेश से सरकार को अब तक 86 अरब रुपये ही मिले हैं। आईडीबीआई बैंक व शिपिंग कॉरपोरेशन की बिक्री से विनिवेश लक्ष्य हासिल करना संभव है।

सब्सिडी खर्च: 4.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान

सब्सिडी पर सरकार को खर्च चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 4.1-4.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकता है। यह 3.8 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से अधिक है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट में कहा, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने की प्रमुख वजह खाद्य और उर्वरक सब्सिडी पर अधिक खर्च करना है। इसके अलावा, भंडारण और परिवहन की ऊंची लागत भी सब्सिडी खर्च बढ़ा रही है।

विपणन वर्ष 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि के बाद बजट आवंटन करीब 10 फीसदी से अधिक होने का अनुमान है।

डॉलर में मजबूती के कारण आयात लागत बढ़ने से अकेले उर्वरक सब्सिडी का बजट 9-10 फीसदी बढ़ सकता है।

2025-26 में घटेगा सरकारी खजाने पर बोझ

अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सब्सिडी का कुल बोझ कम होकर लगभग 4 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। माना जा रहा है कि खाद्य सब्सिडी में बड़ी गिरावट आएगी और यह 2-2.1 लाख करोड़ रुपये के बीच रह सकती है।

आयात लागत के निरंतर दबाव के कारण उर्वरक सब्सिडी 1.7-1.8 लाख करोड़ रह सकती है।

सकल कर्ज 14 लाख करोड़

चालू वित्त वर्ष में सरकार का सकल कर्ज 14.01 लाख करोड़ और शुद्ध उधारी 11.63 लाख करोड़ रह सकती है। अगले वित्त वर्ष में शुद्ध कर्ज घटकर 10.8 लाख करोड़ रुपये रहने की उम्मीद है।

मुंबई-दिल्ली शीर्ष 10 पसंदीदा बाजारों में शामिल; विदेशी निवेश के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र का हुआ सर्वे

परिवहन विशेष न्यूज

सीबीआरई इंडिया ने शुक्रवार को जारी सर्वे में कहा, एशिया-प्रशांत बाजारों में शुद्ध खरीदारी के इरादे में सुधार देखने को मिला है और यह बढ़कर 13 फीसदी पहुंच गई है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने 2025 में अधिक अचल संपत्ति खरीदने की प्राथमिकता जताई है। भारत में भी शुद्ध खरीदारी धारणा तीन फीसदी पर पहुंच गई है।

मुंबई व दिल्ली सीमा पार निवेश के मामले में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष-10 सबसे पसंदीदा बाजारों में शामिल हैं। मुंबई पांचवें और दिल्ली आठवें स्थान पर है। सीबीआरई इंडिया ने शुक्रवार को जारी सर्वे में कहा, एशिया-प्रशांत बाजारों में शुद्ध खरीदारी के इरादे में सुधार देखने को मिला है और यह बढ़कर 13 फीसदी पहुंच गई है। आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने 2025 में अधिक अचल संपत्ति खरीदने की प्राथमिकता जताई है। भारत में भी शुद्ध खरीदारी धारणा तीन फीसदी पर पहुंच गई है। भारत में निवेशक कार्यालय, आवासीय, औद्योगिक और डाटा सेंचर सहित सभी परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करना चाहते हैं।

टोक्यो, सिडनी और सिंगापुर शीर्ष पर

सीमा पार निवेश में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष-10 पसंदीदा बाजारों में टोक्यो पहले स्थान पर है। सिडनी दूसरे, सिंगापुर तीसरे और हो ची मिन्ह सिटी चौथे स्थान पर है। दिल्ली के साथ सियोल, ओसाका व हनोई भी आठवें स्थान पर हैं।

वैश्विक गंतव्य के रूप में भारत सबसे आगे

सीबीआरई के चेयरमैन-सीईओ अंशुमान मैगजीन ने कहा, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विदेशी निवेशकों के पूंजी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि वैश्विक रियल एस्टेट गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती प्रमुखता का प्रमाण है। रियल्टी बाजार के स्थापित और नए दोनों क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह जारी रहने की उम्मीद है। ई-कॉमर्स और त्वरित आपूर्ति सेवाओं की मांग से लॉजिस्टिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

देश में 11.4 अरब डॉलर का रिकॉर्ड इक्विटी निवेश

सीबीआरई के मुताबिक, भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल इक्विटी निवेश 2024 में 11.4 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 54 फीसदी की मजबूत वृद्धि है।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में हुए कुल इक्विटी निवेश में सिंगापुर, अमेरिका और कनाडा की हिस्सेदारी 25 फीसदी से ज्यादा रही। अकेले सिंगापुर का योगदान सर्वाधिक 36 फीसदी रहा।

दो बच्चे होने पर मिलती थी ज्यादा छूट; ₹100 कमाने पर ₹2.25 ही जाते थे जेब में, 1947 से कितना बदला आयकर

परिवहन विशेष न्यूज

आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। सरकार की आमदनी का एक हिस्सा इनकम टैक्स यानी आयकर से आता है। यह टैक्स देश के लोगों को अपनी कमाई से सरकार को देना पड़ता है। आजादी के समय देश में 1500 रुपये तक की आमदनी ही टैक्स फ्री थी। उसके बाद आयकर व्यवस्था में समय-समय पर कई बदलाव किए गए। आइए जानते हैं देश की अब तक की यात्रा में कितना बदला आयकर?

आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। उसके बाद के बजट में केंद्र सरकार की ओर से आमदनी और खर्च का ब्यौरा दिया जाने लगा। सरकार की आमदनी का एक हिस्सा इनकम टैक्स यानी आयकर से आता है। यह टैक्स देश के लोगों को अपनी कमाई से सरकार को देनी पड़ती है। आजादी के समय देश में 1500 रुपये तक की आमदनी ही टैक्स फ्री थी। उसके बाद आयकर व्यवस्था में समय-समय पर कई बदलाव किए गए। देश में एक समय ऐसा भी था जब बच्चों की संख्या के आधार पर किसी व्यक्ति को कितना टैक्स देना पड़ेगा, यह तय होता था। देश में आयकर का इतिहास कई और मायनों में भी दिलचस्प रहा है। आइए जानें इसका दिलचस्प इतिहास।

नौकरीपेशा लोगों के लिए 7 लाख 75 हजार तक की आमदनी टैक्स फ्री

केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री की ओर से किए गए एलानों के बाद अगर किसी नौकरीपेशा करदाता की सालाना आय 7 लाख 75 हजार रुपये तक है, उसे आयकर नहीं चुकाना पड़ता है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये घटाने के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपये रह जाती है। ऐसे में उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि नई टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की आमदनी सरकार ने टैक्स फ्री कर रखी है। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 64000 या 64500 रुपये के आसपास है तो उसे नई कर प्रणाली में कोई आयकर चुकाने की जरूरत नहीं है।

बजट 2025 में वित्त मंत्री से 10 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री करने की हो रही मांग

केंद्रीय बजट 2025 में जानकारों ने वित्त मंत्री से 10 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स के दायरे से अलग रखने की अपील की है। 2023-24 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिविजुअल टैक्सपेयर के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया था। आयकर का दायरा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये (नई टैक्स रिजीम के तहत) कर दिया गया था। इस दौरान सुपर रिच टैक्स को भी घटाकर 37 प्रतिशत कर दिया गया था। वहीं रिटायर्ड कर्मियों के लिए लिव इनकैशमेंट की सुविधा में इजाफा कर उसे तीन लाख से 25 लाख रुपये कर दिया गया था।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में नई टैक्स रिजीम को किया गया डिफॉल्ट

पिछले साल नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है। नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2020 से लागू किया था। नई टैक्स व्यवस्था यानी नई टैक्स रिजीम में नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे लेकिन आयकर में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट समाप्त कर दिए गए थे। भारत में आजादी के बाद से आयकर के मामले में अलग-अलग सरकारों ने कई बदलाव किए हैं। इन बदलावों का आम आदमी पर सीधा असर पड़ा है, क्योंकि आयकर वह राशि है जो किसी व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई में से बचाकर सरकार को देनी पड़ती है।

देश आजाद हुआ तब 1500 रुपये तक की आमदनी थी टैक्स फ्री

आजाद भारत का पहला बजट 16 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। इसे देश के पहले वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। हालांकि यह एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा रिपोर्ट थी। जब देश का पहला बजट पेश किया गया था उस समय देश में 1500 रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री थी। 2023 में मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में यह लिमिट सात लाख रुपये (नई टैक्स रिजिम के तहत) कर दी गई।

शादीशुदा और कुंवारों के लिए था अलग-अलग टैक्स का प्रावधान

1955 में जनसंख्या बढ़ाने के लिए पहली बार देश में शादीशुदा और कुंवारों के लिए अलग-अलग टैक्स फ्री इनकम रखी गई। इसके तहत शादीशुदा लोगों को 2000 रुपये तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं, कुंवारों के लिए यह लिमिट 1000 रुपये ही थी।

आबादी बढ़ाने पर टैक्स छूट देने वाला पहला देश बना भारत

भारत 1958 में बच्चों की संख्या के आधार पर इनकम टैक्स में छूट देने वाला दुनिया का इकलौता देश बना। शादीशुदा होने पर यदि बच्चा नहीं है तो 3000 रुपये तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन, एक बच्चे वाले व्यक्तियों के लिए 3300 रुपये और 2 बच्चों पर 3600 रुपये की आय टैक्स फ्री थी।

एक समय 100 रुपये की कमाई पर लगता था 97.75 रुपये टैक्स

1973-74 में भारत में आयकर की दर सबसे ज्यादा थी। उस समय आयकर वसूलने की अधिकतम दर 85 फीसदी कर दी गई थी। सरचार्ज मिलाकर यह दर 97.75 फीसदी तक पहुंच जाती थी। 2 लाख रुपये की आमदनी के बाद हर 100 रुपये की कमाई में से सिर्फ 2.25 रुपये ही कमाने वाले की जेब में जाते थे। बाकी 97.75 रुपये सरकार रख लेती थी। हालांकि बाद के दौर में विभिन्न सरकारों ने लोगों पर आयकर भार कम करने के लिए बड़े कदम उठाए। फिलहाल देश में आयकर के दो टैक्स रिजीम अमल में हैं। जिसमें नई टैक्स रिजीम के तहत नौकरीपेशा लोगों के लिए करीब 7 लाख 75 हजार रुपये की आमदनी टैक्स के दायरे से बाहर है।

महिलाओं के खाते में सीधे नकद भेजने वाली योजनाओं की सूनामी राज्यों के लिए ठीक नहीं, सामने आया कारण

डीबीटी योजनाओं पर एसबीआई रिपोर्ट: महिलाओं को खाते में सीधे नकद हस्तांतरित करने की योजनाओं का चलन हाल के वर्षों में, विशेष रूप से चुनावों के दौरान काफी बढ़ा है। रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इस तरह की पहल राज्य के वित्त को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती है। एसबीआई की एक रिपोर्ट में इस पर टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है, आइए जानें।

राज्यों की ओर से घोषित महिला केंद्रित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं (सीधे खाते में नकद भेजने वाली योजनाएं) की सुनामी उनकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं को खाते में सीधे नकद हस्तांतरित करने की योजनाओं का चलन हाल के वर्षों में, विशेष रूप से चुनावों के दौरान काफी बढ़ा है। रिपोर्ट में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि इस तरह की पहल राज्य के वित्त को बहुत हद तक प्रभावित कर सकती है।

खाते में पैसे भेजने वाली योजनाएं चुनावी राजनीति से प्रेरित: एसबीआई

एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ₹कई राज्यों की ओर से महिलाओं को सीधे खाते में लाभ भेजने वाली योजनाओं की घोषणा उनके वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है।₹ रिपोर्ट में कुछ राज्यों की ओर से की गई ऐसी घोषणाओं को विशुद्ध चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया गया है और कहा गया है कि ऐसी योजनाओं की सुनी चुनिंदा राज्यों के वित्त को नुकसान पहुंचा सकती है₹

रिपोर्ट के नुसार आठ राज्यों में लागू की गई इन योजनाओं की कुल लागत बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई है, यह राशि इन राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 3 से11 प्रतिशत के बीच है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओडिशा जैसे कुछ राज्य अधिक गैर-कर राजस्व और ऋणों की कमी के कारण इन लागतों का वहन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन कई राज्यों को इस मामले में राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

कर्नाटक और बंगाल की इन योजनाओं पर रिपोर्ट में की गई टिप्पणी

रिपोर्ट में कर्नाटक का उदाहरण देते हुए बताया गया है कि वहां की गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह दी जाती है, के लिए 28,608 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 11 प्रतिशत है।

रिपोर्ट में आगे पश्चिम बंगाल की भी चर्चा की गई है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल की लक्ष्मीर भंडार योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान देती है, की लागत 14,400 करोड़ रुपये या राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 6 प्रतिशत है।

एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, ₹दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जिसमें वयस्क महिलाओं (कुछ श्रेणियों को छोड़कर) को 1,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया है, पर करीब 2,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह राशि राजस्व प्राप्तियों का 3 प्रतिशत है।

राज्यों को सुझाव- योजना की घोषणा से पहले अपने वित्तीय हालत की करें पड़ताल

एसबीआई की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के खाते में सीधे नकद भेजने वाली योजनाओं का चलन बढ़ने से केंद्र पर भी ऐसी योजनाओं से जुड़ी नीतियों को अपनाने का दबाव बन सकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि केंद्र सरकार से राज्यों को मिलने वाले अनुदान से बनी एक सार्वभौमिक आय हस्तांतरण योजना, ऐसे वादों का अधिक टिकाऊ विकल्प हो सकती है।

रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि ऐसा करने से बाजार को बाधित करने वाली सब्सिडी को कम करने में भी मदद मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार नकद हस्तांतरण योजनाओं को महिलाओं को सशक्त बनाने और चुनावी समर्थन हासिल करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि राज्य ऐसे कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने से पहले अपने राजकोषीय स्वास्थ्य और उधार लेने के पैटर्न पर विचार करें।

बजट में कृषि, एमएसएमई, घरेलू खपत और रोजगार सृजन को प्राथमिकता की उम्मीद, विशेषज्ञों की है यह राय

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी बजट में वित्त मंत्री किस क्षेत्र के लिए क्या घोषणाएं करेगी और क्या आम आदमी को महंगाई से राहत मिलेगी या करों का भर बढ़ेगा। फिलहाल यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जानकारों ने अपनी मांगें भी सरकार के सामने रखी हैं। बाजार के विशेषज्ञों को उम्मीद है कि बजट में भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ऐसे उपायों पर ध्यान दिया जाएगा जो समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। बजट में कृषि, एमएसएमई, घरेलू खपत और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। जानकारों का अनुमान है कि घरेलू खर्च को बढ़ावा देने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बाजार को विशेषज्ञों की बजट से उम्मीद

श्रीराम एएमसी के वरिष्ठ फंड मैनेजर दीपक रामाराजू का कहना है कि जीडीपी की वृद्धि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 7- तिमाही के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई है। उम्मीद है कि इसके लिए सरकार विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों को प्राथमिकता इस बजट में देगी। विशेषकर कम आय वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है। वहीं बजट में फोकस के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश, टिकाऊ ऊर्जा की पहल, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और रक्षा तथा रेलवे पर निरंतर खर्च शामिल होने की संभावना है। यह सभी क्षेत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एसएमई की मांग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार इस बजट में स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर भी व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर स्लैब और सरलीकृत कर संरचना पर ध्यान के साथ डिस्पोजेबल आय में बढ़ोतरी कर सकती है।

बाजार के नजरिए से देखे तो बजट में विकास केंद्रित खर्च और राजकोषिय के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। विकासोन्मुखी बजट जरूरी है, लेकिन सरकार को लोकलुभावन उपायों के मामले में सावधानी बरत सकती है, क्योंकि ऐसे फैसले राजकोषीय घाटे को बढ़ा सकते हैं और रुपये को और कमजोर कर सकते है, इससे दरों में कटौती को सीमित करके आर्थिक सुधार में देरी हो सकती है। राजकोष पर दबाव से विकास की गति कम होने के संकेत मिलते है जो बाजार में बिकवाली का कारण बन सकता है।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को अपनाने की जरुरत

सैमको सिक्योरिटीज के संस्थापक जिमीत मोदी कहते हैं, अगर भारत को 2047 तक सही मायने में ₹विकसित भारत₹ बनने और बेहतरीन रक्षा क्षमताओं के अलावा विकसित अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं, तो देश को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं अपनाने की जरूरत है जैसे कुशल सार्वजनिक बाजारों के साथ साथ मुक्त मुद्रा का भी विकास किया जाना चाहिए। जहां तक सार्वजनिक बाजारों का सवाल है तो कुछ साल पहले भारत सभी मोर्चों पर बेहतरीन बाजार रहा। बाजार में अधिक लिक्विडिटी रही और उस आधार पर हमारे बाजार अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अधिक प्रीमियम का लाभ उठा रहे थे। लेकिन पिछले दो सालें में बजट और उसके बाहर के कराधान के मोर्चे पर और विनियामक मोर्चे पर उठाए गए कदमों की वजहों से भारत के प्रीमियम को अन्य उभरते बाजारों की तुलना में झटका लगा है। इसने बाजार की लिक्विडिटी को प्रभावित किया है।

भारतीय पूंजी बाजार के इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड पर विनियामक कार्रवाई की श्रृंखला और सभी क्षेत्रों में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) में बढ़ोतरी ने बाजार में तरलता को पहले की अवधि की तुलना में 30-40 प्रतिशत तक कम कर दिया है। इसलिए मुद्रा व डेरिवेटिव बाजारों को खोला जाना चाहिए क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए महत्वपूर्ण है। पूंजी बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए, सरकार को वायदा, विकल्प और अन्य उपकरणों पर एसटीटी दरों को तर्कसंगत बनाना चाहिए। इससे सरकार को कुछ हद तक राजस्व का नुकसान हो सकता है, लेकिन बढ़ी हुई तरलता और बढ़ी हुई भागीदारी के माध्यम से आने वाले नए प्रवाह से इसकी भरपाई हो जाएगी।

पूंजी व्यय और खपत को बढ़ावा देने में संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रेली ने कहा शहरी मांग और निवेश गतिविधियों में नरमी की बीच भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 23-24 में 8.2 प्रतिशत से वित्त वर्ष 24-25 में 6.4 प्रतिशत तक कम होने का अनुमान है। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य से लगभग 1.4 ट्रिलियन रुपये कम रहने की संभावना जताई है, जिससे वित वर्ष 2025 में 4.8 प्रतिशत अपेक्षित राजकोषीय घाटा होने की संभावना है, जो बजट में निर्धारित 4.9 प्रतिशत से काफी कम है। इसलिए आगामी बजट में देश की विकास की गति को बनाए रखने के लिए लगातार पूंजी व्यय और खपत को प्रोत्साहित करने में संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती वित्त मंत्री के सामने है। समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, बजट में कृषि, एमएसएमई, घरेलू खपत और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है। घरेलू खर्च को बढ़ावा देने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आधा से अधिक हिस्सा है। हम उम्मीद करते हैं कि बजट में विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपभोग प्रोत्साहन और लक्षित बुनियादी ढांचे के खर्च के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाया जाएगा।

गणतंत्र@75: यूं ही नहीं विश्व गुरु बन रहा देश, 75 साल के लंबे सफर में बहुत कुछ बदला, पढ़ें विकासशील भारत की कहानी

गणतंत्र दिवस 2025 देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद से राष्ट्र निर्माण के लिए जो ऊर्जा दिखी वह पिछले साढ़े सात दशक से लगातार मजबूत होती जा रही है। उपलब्धियों की बढ़ती श्रृंखला के पीछे हमारा संविधान ही है जो हमें अनुशासित लगनशील और मेहनतकश बनाता है। आइए जानते हैं पिछले 75 सालों में देश में क्या कुछ हुआ।

नई दिल्ली। अंग्रेजों से आजादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्रता के सही मायनों को हमने 1950 में जीना शुरू किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के बाद से अपने तौर-तरीकों से राष्ट्र निर्माण के लिए जो ऊर्जा दिखी, वह पिछले साढ़े सात दशक से लगातार मजबूत होती जा रही है।

अपने अपार मानव संसाधन के बलबूते आत्मनिर्भरता की राह पर विकासशील से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हो चला है। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हर वैश्विक मंच पर हमारी आवाज का मतलब निकाला जाने लगा है।

उपलब्धियों की बढ़ती श्रृंखला के पीछे हमारा संविधान ही है जो हमें अनुशासित, लगनशील और मेहनतकश बनाता है।

इसने हमें अधिकार दिए जो कर्तव्यों की भी याद दिलाई है। इन्हीं संविधान प्रदत्त अधिकारों के दम पर ही आज फिर से भारत विश्व गुरु की अपनी पुरातन छवि के रूप में देखा जाने लगा है। नागरिक कल्याण और देश निर्माण से जुड़े ऐसे ही मील के पत्थरों को याद कर रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह...

सबको मतदान का अधिकार

संविधान लागू होने से ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग गठित किया गया था। यह कोई संयोग नहीं है कि भारतीय गणराज्य का पहला बड़ा विधायी उपाय सबको मतदान का अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को लागू करना था।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के जरिये ऐसा किया गया। 1950 के अधिनियम ने मतदाता सूची तैयार करने और निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने की प्रक्रिया और मशीनरी निर्धारित की, वहीं 1951 के अधिनियम ने चुनाव कराने के लिए अधिसूचना से लेकर परिणामों की घोषणा तक का प्रविधान किया। इन अधिनियमों में अब तक कई संशोधन किए गए हैं। जैसे प्रचार की अवधि को एक महीने से घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।

यही नहीं देश में कृषि सुधार कानून भी लाया गया

हिंदू कोड बिल

डा. भीमराव आंबेडकर ने फरवरी 1951 में हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया। इस बिल का इतना विरोध हुआ कि उन्होंने सात महीने के भीतर ही कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। 1952

में पहला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ही नेहरू सरकार ने हिंदू सुधार एजेंडे को आगे बढ़ाया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क्रांतिकारी था। इसने बहुविवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया और एक ऐसे समुदाय में तलाक की अवधारणा पेश की, जो मानता था कि विवाह एक संस्कार है जो एक जोड़े को जन्म-जन्मांतर तक एक साथ बांधता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ने महिलाओं को पारंपरिक रूप से दिए गए सीमित अधिकारों के बजाय पारिवारिक संपत्ति में उनके हिस्से के लिए पूर्ण स्वामित्व प्रदान किया।

अस्पृश्यता पर प्रहार

संविधान ने पहली बार अस्पृश्यता को समाप्त किया। अस्पृश्यता के विभिन्न रूपों को दंडित करने वाला कानून, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया गया। यह कानून जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव के मामलों तक ही सीमित था, इसलिए राजीव गांधी सरकार ने जाति के आधार पर की जाने वाली हिंसा से निपटने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 बनाया।

राज्यों का पुनर्गठन

1956 में लागू किए गए सातवें संविधान संशोधन ने भाषाई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणाएं पेश कीं।

भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग पूरे देश में हो रही थी, लेकिन 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु की भूख हड़ताल से इसमें तेजी आई मिली थी। उनकी भूख हड़ताल मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जिलों को मिला कर आंध्र राज्य बनाने के लिए थी।

1953 में आंध्र राज्य के गठन के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) की नियुक्ति की गई। आयोग शुद्ध रूप से भाषाई आधार पर सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के विचार से सहमत नहीं था।

हालांकि, एसआरसी ने हैदराबाद को राजधानी बनाकर एक अलग तेलंगाना राज्य के गठन की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने आंध्र के नेताओं के दबाव में झुकते हुए 1956 में दो तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकर आंध्र प्रदेश बना दिया।

एसआरसी ने सिफारिश की कि बांबे गुजराती और मराठी भाषी जिलों को शामिल करते हुए एक संयुक्त राज्य बना रहे, लेकिन सरकार ने 1960 में सभी मराठी भाषी जिलों को मिलाकर महाराष्ट्र बनाने की मांग मान ली।

दल बदल विरोधी कानून

राजीव गांधी की सरकार 1985 में 52वें संविधान संशोधन के रूप में लंबे समय से लंबित दलबदल विरोधी कानून लेकर आई। इसने दलबदल को मुश्किल बनाया लेकिन इसकी गुंजाइश अब भी थी। राजनेताओं ने एक खामी का फायदा उठाया, जिसके तहत विधायक दल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के दलबदल को विभाजन माना जाता था। वाजपेयी सरकार ने 2003 में 91वें संविधान संशोधन के साथ इस खामी को दूर कर दिया। अब दलबदल केवल विलय के रास्ते से ही हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि विधायक दल के कम से कम दो तिहाई सदस्य दूसरे के साथ विलय के लिए सहमत हों।

पंचायती राज कानून

ग्राम स्वराज (ग्राम स्वशासन) का गांधीवादी सपना 1992 में साकार हुआ। केंद्र सरकार ने सरकार ने 73वें संविधान संशोधन को आगे बढ़ाया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने के अलावा, पंचायती राज कानून ने महिलाओं के लिए एक तिहाई निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित किया। यह एक ऐसा प्रविधान था जिसे शासन के स्तर पर बार बार रोका गया था। इसके बाद 74 वें संविधान संशोधन के जरिये शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं को संस्थागत बनाया गया।

सूचना का अधिकार

2005 में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) लागू हुआ। इसने शासन-प्रशासन की तस्वीर बदलकर रख दी। यह कानून आम जनता के लिए एक ऐसा हथियार साबित हुआ, जिसने पारदर्शिता और जवाबदेही की नई इबारत लिखी। आरटीआइ ने हर नागरिक को यह अधिकार दिया कि वे सरकारी प्राधिकरणों से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकें।

पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड कहां हुई थी? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने थे मुख्य अतिथि; पढ़िए रोचक किस्सा

देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो मुख्य अतिथि बने। जब देश का पहला गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा था तब भी इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त ये परेड कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि इरविन एम्फीथिएटर में आयोजित की गई थी। ये जगह अब नेशनल स्टेडियम कही जाती है।

नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस के समारोह पर हर बार एक थीम होती है। इस बार संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास की थीम रखी गई थी। इसके लिए कर्तव्य पथ पर विशाल तिरंगे की थीम वाले बैनर लगाए गए हैं।

हालाँकि, भारतीय गणराज्य की शुरुआत का पहला समारोह राजपथ (जिसे अब कार्तव्य पथ कहते हैं) पर आयोजित नहीं किया गया था। लेकिन देश को पहला राष्ट्रपति मिलने के बाद इसे 1930 के दशक के इरविन एम्फीथिएटर में आयोजित किया गया था।

इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि

1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। आज 75 साल बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस साल की औपचारिक परेड में मुख्य अतिथि बने। इंडोनेशिया से एक एक मार्चिंग दल और एक बैंड दल भी परेड में शामिल हुआ।

26 जनवरी, 1950 की रात प्रतिष्ठित सार्वजनिक इमारतें, पार्क और रेलवे स्टेशन सभी रोशनी से चकाचौंध हो गए। ऐसा लगने लगा, जैसे राजधानी एक 'परीलोक' में बदल गई हो।

फौजी अखबार ने लिखी रिपोर्ट

फौजी अखबार (अब सैनिक समाचार) ने अपने 4 फरवरी के लेख 'बर्थ ऑफ ए रिपब्लिक' में लिखा, 'गवर्नमेंट हाउस में ऊंचे गुंबदों और शानदार रोशनी वाले दरबार हॉल में आयोजित समारोह में भारत को एक संप्रभु डेमोक्रेटिक घोषित किया गया था।'

इसमें आगे लिखा गया, 'गुरुवार, 26 जनवरी 1950 की सुबह ठीक 10 बजकर 18 मिनट पर भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया। छह मिनट बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। भारतीय गणराज्य के जन्म और इसके पहले राष्ट्रपति की घोषणा सुबह 10:30 बजे के तुरंत बाद 31 तोपों की सलामी के साथ की गई।'

इस प्रभावशाली शपथ ग्रहण समारोह में सेवानिवृत्त गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी ने 'भारत, यानी भारत' गणराज्य की उद्घोषणा पढ़ी।

गवर्नर जनरल का भाषण

मिलिट्री जर्नल ने गवर्नर-जनरल के भाषण का

हवाला देते हुए लिखा, 'यह संविधान द्वारा घोषित किया गया है कि इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा, जिसमें संघ के भीतर वे क्षेत्र शामिल होंगे जो अब तक गवर्नर के प्रांत, भारतीय राज्य और चीफ कमिश्नर के प्रांत थे'

इसके बाद राष्ट्रपति ने शपथ ली और संक्षिप्त भाषण दिया, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, 'आज, हमारे लंबे और विचित्र इतिहास में पहली बार हम उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केप कोमोरिन तक, पश्चिम में काठियावाड़ और कच्छ से लेकर पूर्व में कोकोनाडा और कामरूप तक इस विशाल भूमि को एक संविधान और एक संघ के तहत ला सके हैं। जो इसमें रहने वाले 320 मिलियन से अधिक पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है।'

जश्न में डूब गया था देश

राजेंद्र प्रसाद के भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते ही देश जश्न में डूब गया। इरविन एम्फीथिएटर को बाद में नेशनल स्टेडियम के तौर पर विकसित कर दिया गया। इरविन एम्फीथिएटर का निर्माण 1933 में भावनगर के तत्कालीन महाराजा के उपहार के रूप में किया गया था।

उन्होंने इसके निर्माण के लिए 5 लाख रुपये का दान दिया था और इसे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड विलिंगडन द्वारा ओपन किया गया था। एम्फीथिएटर का नाम भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड इरविन के नाम पर रखा गया था।

पहले गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में 100 साल से अधिक पुराने फौजी अखबार ने लिखा था, 'राष्ट्रपति ठीक 2:30 बजे 35 साल पुराने विशेष कोच में सवार होकर राज्य के गवर्नमेंट हाउस (अब राष्ट्रपति भवन) से बाहर निकले, जिसे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के साथ धीमी गति से चलने वाले छह मजबूत ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों द्वारा खींचा गया।'

सड़कों पर होने लगी जय-जयकार

इसके मुताबिक, 'जैसे ही जुलूस इरविन एम्फीथिएटर से होकर गुजरा, सड़कों पर जय के नारे गूंजने लगे। राजेंद्र प्रसाद ने जनता के हर्षोल्लासपूर्ण अभिवादन का गर्मजोशी से और हाथ जोड़कर जवाब दिया।

15,000 लोगों की क्षमता वाला यह एम्फीथिएटर भारत के हालिया इतिहास की सबसे शानदार सैन्य परेडों में से एक का गवाह बना। आयोजन स्थल को खूबसूरती से सजाया गया था और स्टैंड बेहतरीन पोशाक पहने लोगों से भरे हुए थे।

तीन सशस्त्र बलों और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सामूहिक बैंडों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि बलों और देशी टुकड़ियों और रेजिमेंटों की इकाइयों ने इस गंभीर अवसर में रंग और सटीकता जोड़ दी।

इस बार तिरंगा तट से दूर 10 द्वीपों पर त्रिरंगा फहराया गया

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : कल पूरे देश में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस बार प्रदेश में गणतंत्र दिवस भव्य होगा। पहली बार गणतंत्र दिवस ओडिशा के तट से दूर 10 द्वीपों पर मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा डीजी और आईजी सम्मेलन में इस मुद्दे पर बोलने के बाद तटरक्षक बल ने स्थान की पहचान कर ली है।इस बीच, राज्य के सुरक्षा महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने शुक्रवार सुबह भुवनेश्वर स्थित शाखा कार्यालय में तटरक्षक कमांडर, पूर्वी समुद्र तट, एडीजी डैनी मिशेल से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने डीजीपी के साथ तटीय सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर चर्चा की। इसके अतिरिक्त, बैठक में आने वाले दिनों में तटीय सुरक्षा के लिए दोनों विभागों के बीच उचित समन्वय के साथ काम करने पर भी विचार व्यक्त किए गए। आदेशों के अनुसार तटीय क्षेत्रों में गश्त, हवाई गतिविधियों की निगरानी तथा सम्पूर्ण तटीय नियंत्रण प्रणाली पर अधिक जोर दिया गया है। बैठक में ओडिशा पुलिस को हर संभव सहयोग प्रदान करने की तटरक्षक बल की इच्छा पर चर्चा की गई।

आने वाले दिनों में तटरक्षक बल और ओडिशा पुलिस के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक विशेष बोर्ड का गठन किया जाएगा। इन दोनों विभागों के अधिकारी पूरे तटीय क्षेत्र की गहन तलाशी लेंगे। डीजीपी ने मीडिया को बताया कि समुद्र तट स्थित पुलिस थाने को नावें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, आने वाले दिनों में तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कर्मियों को समुद्र तट स्टेशन पर नियुक्त किया जाएगा। ओडिशा पुलिस और तटरक्षक बल के साथ स्थापित दीर्घकालिक संबंधों को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयास किए जाएंगे।गणतंत्र दिवस पर समुद्र में स्थित 10 द्वीपों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। डीजीपी श्री खुरानिया ने मीडिया को बताया कि इस उद्देश्य के लिए द्वीपों की पहचान कर ली गई है।

भारी बारिश और घना कोहरा... बदल रहे मौसम के हालात, गर्मी के बाद फिर बढ़ेगी सर्दी

सर्दी के मौसम में निकल रही तेज धूप अब आपको ज्यादा दिन नसीब नहीं होने वाली है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश बिहार नगालैंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में घना कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं पहाड़ों और मैदानी इलाकों में 29 जनवरी के बाद से ही भारी बारिश हो सकती है।

नई दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों से निकल रही तेज धूप ने लोगों को सर्दी के महीने में गर्मी का अहसास कराया है। सर्दी कम महसूस होने से लोग बेहद खुश हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन की खुशी भी नहीं।

दरअसल एक नहीं, बल्कि दो-दो वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स की वजह से बहुत जल्द मौसम पूरी तरह बदलने जा रहा है। इससे कई क्षेत्रों में भयंकर बारिश हो सकती है और कुछ हिस्से घने कोहरे की चपेट में भी आ सकते हैं।

1 फरवरी तक बारिश की संभावना

बता दें कि पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स 29 जनवरी से सक्रिय होगा। वहीं दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी तक आने की संभावना है। इनके चलते 29 जनवरी से 1 फरवरी तक भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में बारिश की संभावना है।

इसके पहले बीते दिन हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में शीतलहर देखने को मिली है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में घना कोहना बना रहा।

तापमान में होगी बढ़ोतरी

वेस्टर्न डिस्टर्बेन्स की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, कोस्टल आंध्र, यनम और रायलसीमा में भी अगले दो दिनों में भारी बारिश हो सकती है। इनके अलावा 29 जनवरी से 1 फरवीर तक पहाड़ी राज्यों और 30 जनवरी से 1 फरवरी तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है।

अगले दो दिनों में उत्तर पश्चिम, मध्य भारत और महाराष्ट्र में तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में दो से चार डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों में तापमान में वृद्धि होगी।

इन राज्यों में रहेगा कोहरा

हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब में अगले दो दिनों में शीतलहर चलने का अनुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नगालैंड और कुछ नॉर्थ-ईस्ट राज्यों में 28 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है।

बिहार में ये कोहरा 29 जनवरी तक देखने को मिलेगा। बता दें कि फिलहाल उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 5-10 डिग्री के बीच बना हुआ है। मैदानी इलाकों की बात करें, तो राजस्थान के चुरू में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया, जो 3.6 डिग्री सेल्सियस था।

'किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए', गणतंत्र दिवस पर बोले आरएसएस चीफ

गणतंत्र दिवस के मौके पर आरएएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से खास अपील की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि सद्भाव से रहने के लिए सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सौहा र्द से रहने की कुंजी सामंजस्य है।

मुंबई। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सौहार्द्र एवं सद्भाव से रहने के लिए सामंजस्य बेहद महत्वपूर्ण है। किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

दरअसल, रविवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक कालेज में गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के साथ-साथ यह अवसर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद करने का भी है।

एकजुटता से जीना चाहिए: भागवत

अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि विविधता के कारण भारत के बाहर संघर्ष हो रहे हैं। हम विविधता को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। आपकी अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन आपको एक-दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यदि आप जीना चाहते हैं तो आपको एकजुटता से जीना चाहिए। यदि आपका परिवार दुखी है तो आप खुश नहीं रह सकते। इसी तरह, यदि कोई शहर संकट का सामना कर रहा है तो परिवार खुश नहीं रह सकता।

राष्ट्र के विकास के लिए समानता जरूरी

आरएसएस प्रमुख ने व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के सम्मान और दमन से मुक्ति के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।

किसी का नहीं होना चाहिए दमन

भागवत ने कहा कि हम चाहते हैं कि व्यक्ति आगे बढ़े और इसके लिए हमें स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है। किसी का भी दमन नहीं होना चाहिए। सभी को अवसर मिलना चाहिए और बंधुत्व के साथ लोग आगे बढ़ेंगे और समाज में अपनी सफलता का प्रसार करेंगे।

उन्होंने कहा कि विविधता के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मतभेदों का सम्मान किया जाना चाहिए और सौहार्द्र से रहने की कुंजी सामंजस्य है ।

युवाओं से की ये अपील

उन्होंने युवा पीढ़ी से उपलब्धियां हासिल करने और अपनी सफलता का उपयोग देश की बेहतरी के लिए करने की अपील की। उन्होंने कहा कि संघ समाज में सभी अच्छे कामों का समर्थन करता है। हम किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि या रंग नहीं देखते हैं, बल्कि केवल अच्छे कामों का समर्थन करते हैं।

उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास और राष्ट्रीय रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति समर्पित व्यक्तियों के प्रयासों का परिणाम है। हालांकि, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत को अपने सपनों का देश बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023